अमर उजाला
प्रवाह
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948
आगरा ■ मंगलवार, 25 फरवरी 2025

बिजली के बाद एआई सबसे अधिक परिवर्तनकारी तकनीक होगी।
-एरिक श्मिट

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधे व्यापार की शुरुआत वहां हावी हो रहे कट्टरपंथी माहौल की अनिवार्य परिणति है। उपमहाद्वीप की भू-राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन भारत के लिए यह समय सतर्क कूटनीति अपनाने का जरूर है।

बांग्लादेश की चाल

बांग्लादेश में शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद पहले पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियमों में राहत, दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की मुलाकात और अब पहली बार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधे व्यापार की शुरुआत से बांग्लादेश के पाकिस्तान की ओर बढ़ते झुकाव की ही पुष्टि होती है, जिससे दक्षिण एशिया की आर्थिक और कूटनीतिक तस्वीर में महत्वपूर्ण बदलाव का भी संकेत मिलता है। भारत के नजरिये से देखें, तो यह क्षेत्रीय व्यापार, राजनीतिक समीकरणों और भू-राजनीतिक संतुलन पर भी व्यापक असर डाल सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत और बांग्लादेश चार हजार किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा साझा करते हैं और दोनों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते भी रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। पर बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बहाने शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार के मुखिया बनने के साथ ही भारत-बांग्लादेश संबंधों में कड़वाहट तो आनी शुरू हुई ही, सोमवार को कॉक्स बाजार एयरफोर्स बेस पर हुआ हमला भी बताता है कि देश में कुछ ठीक नहीं चल रहा। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट की उचित ही दो वजहें बताते हैं। एक, अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म और दो, बांग्लादेश की राजनीति, जिसमें उन्हें तय करना होगा कि वे भारत से कैसे रिश्ते चाहते हैं। बांग्लादेश को समझना होगा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उनका आंतरिक मामला नहीं, बल्कि यह पूरे उपमहाद्वीप में शांति व स्थिरता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। दो महीने पहले भारतीय विदेश सचिव की बांग्लादेश यात्रा पर दोनों देशों ने साथ मिलकर काम करने और विभिन्न मुद्दों पर संतुलित विचार करने पर सहमति जताई थी। इसके बावजूद, पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज कट्टरपंथी तत्वों का अलग ही रवैया दिखा है। हालांकि यह पूरी तरह से अप्रत्याशित भी नहीं है, क्योंकि बीएनपी और जमात पहले भी खुलकर भारत का विरोध करते रहे हैं। अगर पाकिस्तान के साथ उसका यह सहयोग आगे बढ़ता है, तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि बांग्लादेश अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं और भारत के साथ रिश्तों को कैसे संतुलित करता है। दूसरी तरफ, भारत के लिए भी यह देखना जरूरी होगा कि बांग्लादेश का पाकिस्तान-प्रेम कौन-सी करवट लेगा। चीनी दखल के पहलू को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा भारत के लिए यह समय सतर्क और सक्रिय कूटनीति अपनाने का है।

एआई परिदृश्य में भारत कहां है

सरकार का सक्रिय रुख 1.2 अरब डॉलर के भारत एआई मिशन जैसी पहलों द्वारा चिह्नित 'संप्रभु एआई' हासिल करने की उसकी महत्वाकांक्षा को रेखांकित करता है। लेकिन भारत को पहले से स्थापित वैश्विक खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी खूबियों को मजबूत और खामियों को दूर करना होगा।

पेरिस में हाल ही में हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की, उन प्रमुख विश्व नेताओं में से थे, जिन्होंने सम्मेलन के अंत में संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। वैश्विक सभा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के विकास के मार्गदर्शन पर आम सहमति बनाने की मांग की। सूचीबद्ध प्राथमिकताओं में से एक एआई को 'खुला, समावेशी, पारदर्शी, नैतिक, सुरक्षित और भरोसेमंद' बनाने की प्रतिबद्धता पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया, लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं। हर कोई एआई को समान रूप में नहीं देखता। अमेरिका और ब्रिटेन ने शिखर सम्मेलन घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। इस जटिल और लगातार बदलते एआई परिदृश्य में भारत कहां है और कौन-सी चुनौतियां उसके सामने हैं? हाल ही में भारत दौरे पर आए ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा था, 'भारत सामान्य रूप से एआई, खासकर ओपनएआई के लिए एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बाजार है। यह हमारा दूसरा सबसे बड़ा बाजार है; हमने पिछले वर्ष यहां अपने उपयोगकर्ताओं की संख्या तीन गुना कर दी है।'

पत्रलेखा चटर्जी
वरिष्ठ पत्रकार

चीन एआई परिदृश्य में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है- चीनी एआई फर्म डीपसीक ने हाल ही में अपने कम लागत वाले ओपन-सोर्स बड़े भाषा मॉडल के साथ उद्योग में खलबली मचाने और अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों को चुनौती देने के लिए वैश्विक सुर्खियां बटोरीं। लेकिन सवाल यह है कि एआई के इस पूरे परिदृश्य में भारत कहां है? पिछले साल, भारत में 245 अरब डॉलर के प्रौद्योगिकी उद्योग की शीर्ष संस्था नैसकॉम (नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज) ने कहा था कि भारतीय एआई बाजार बढ़ रहा है और एआई कौशल उद्योग तथा राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। नैसकॉम और डेलॉइट की एक संयुक्त रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की एआई प्रतिभा पूल वर्तमान में लगभग छह लाख से बढ़कर 2027 तक 12.5 लाख से अधिक होने की उम्मीद है। सरकार का सक्रिय रुख 1.2 अरब डॉलर के भारत एआई मिशन जैसी पहलों द्वारा चिह्नित 'संप्रभु एआई' हासिल करने की उसकी महत्वाकांक्षा को रेखांकित करता है। भाषिनी जैसी पहल- जो एक एआई-संचालित भाषा अनुवाद उपकरण है, जिसे क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है- समावेशिता के लिए एआई का लाभ उठाने की भारत की क्षमता का उदाहरण है। हालांकि, खुद की क्षमताओं के बावजूद भारत की अपनी एआई यात्रा में काफी बाधाएं भी हैं। मौजूदा दौर में उन्नत सेमीकंडक्टर चिप तकनीकी नवाचार की रीढ़ हैं।

एआई, विशेषकर डीप लर्निंग को बड़े डाटासेट को संसाधित करने और जटिल गणना करने के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटेशनल शक्ति की जरूरत होती है। यह वह जगह है, जहां सेमीकंडक्टर, विशेष रूप से जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट), टीपीयू (टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट) और एएसआईसी (एप्लिकेशन-स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट) जैसे माइक्रोचिप चलन में आते हैं। भारत की प्रमुख चुनौतियों में एक आयातित सेमीकंडक्टर पर निर्भरता है। भले ही भारत ने पूरी तरह से आयात पर निर्भर खिलाड़ी से सेमीकंडक्टर्स का निर्माता बनने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किया है, लेकिन जब ताइवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका जैसे स्थापित वैश्विक खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की बात आती है, तो इस उद्योग की अत्यधिक पूंजी-गहन प्रकृति भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अन्य विशेषज्ञ बताते हैं कि भले ही राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन और एनवीडिया जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी का उद्देश्य महत्वपूर्ण कमियों को दूर करना है, फिर भी एक आत्मनिर्भर हार्डवेयर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए निरंतर निवेश और नवाचार की आवश्यकता होती है। भारत को एआई अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमताओं के निर्माण और उन्नत कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने की आवश्यकता है। दूसरी चुनौती मानव संसाधन है। हालांकि, इंडिया एआई मिशन जैसी पहलें इस कमी को दूर कर रही हैं, लेकिन देश के भीतर प्रतिभा को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। एक अन्य जरूरी मुद्दा शहरी-ग्रामीण डिजिटल विभाजन है। बंगलूरू और हैदराबाद जैसे बड़े शहर नवाचार के रूप में उन्नति कर रहे हैं, जबकि विशाल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उपकरणों और अवसरों तक पहुंच का अभाव है। भाषिनी जैसे प्रोजेक्ट का लक्ष्य एआई का लोकतंत्रीकरण करना है, लेकिन इन प्रयासों को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी, शिक्षा और सामर्थ्य में प्रणालीगत निवेश की आवश्यकता है। यदि भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि एआई का लाभ उसके सभी नागरिकों को मिले, न कि चुनिंदा लोगों को, तो डिजिटल विभाजन को पाटना होगा।

एआई की परिवर्तनकारी क्षमता अन्य जोखिम भी पैदा करती है, खासकर भारत जैसे विविध और विशाल आबादी वाले देश के लिए। ऐसे देश में जहां युवा बेरोजगारी गंभीर चुनौती बनी हुई है, स्वचालन लाखों नौकरियों को विस्थापित कर सकता है, खासकर विनिर्माण और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में, जो कार्यबल के एक बड़े हिस्से को रोजगार देते हैं। मजबूत रीस्किलिंग कार्यक्रमों के बिना ये व्यवधान सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को गहरा कर सकते हैं। भारत को अपने कार्यबल को बदलते नौकरी बाजार के लिए तैयार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रमों में निवेश करने की आवश्यकता है कि एआई के लाभों को समान रूप से साझा किया जाए। डिजिटल सिस्टम पर भारत की निर्भरता इसे साइबर सुरक्षा खतरों के प्रति भी संवेदनशील बनाती है। चूंकि एआई डाटा पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, इसलिए डाटा गोपनीयता, संरक्षण और सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। भारत का डाटा संरक्षण कानून अब भी विकसित हो रहा है, और नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा व एआई तकनीकों का दुरुपयोग रोकने के लिए और अधिक मजबूत नियमों की आवश्यकता है। वैश्विक एआई परिदृश्य में भारत की प्रतिभा, नवाचार और डाटा में इसकी ताकत इसे एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है, जबकि इसकी कमजोरियां रणनीतिक योजना और समावेशी नीति निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। भारत में न केवल राष्ट्रीय प्रगति के लिए एआई का उपयोग करने की क्षमता है, बल्कि वैश्विक मंच पर न्यायसंगत और टिकाऊ एआई विकास के लिए एक उदाहरण भी स्थापित किया जा सकता है। दुनिया देख रही है। edit@amarujala.com

जीवन धारा

आचार्य रजनीश

जो व्यक्ति वास्तव में ध्यान करने वाला है, वह खेलपूर्ण होगा। जीवन उसके लिए मस्ती, लीला और खेल है। वह जीवन का परम आनंद लेता है। वह गंभीर नहीं होता, विश्रामपूर्ण होता है।

ध्यान में ही जीवन का परम आनंद

ध्यान में कुछ अनिवार्य तत्व हैं, विधि कोई भी हो, वे अनिवार्य तत्व हर विधि के लिए आवश्यक हैं। पहली है विश्रामपूर्ण अवस्था : मन के साथ कोई संघर्ष नहीं, मन पर कोई नियंत्रण नहीं, कोई एकाग्रता नहीं। दूसरा, जो भी चल रहा है, उसे बिना किसी हस्तक्षेप के बस शांत सजगता से देखो भर। शांत होकर, बिना किसी निर्णय और मूल्यांकन के, बस देखते रहो। तुम्हारे भीतर की सारी हलचल समाप्त हो जाती है। तुम हो, लेकिन 'मैं हूं' का भाव नहीं है। बस एक शुद्ध आकाश है। ध्यान की एक सौ बारह विधियां हैं, मैं उन सभी विधियों पर बोल रहा हूं। उनकी संरचना में भेद है, परंतु उनके आधार वही हैं: विश्राम, साक्षित्व और एक निर्विवेचनापूर्ण दृष्टिकोण। लाखों लोग ध्यान से चूक जाते हैं। लगता है, ध्यान बस उन्हीं लोगों के लिए है, जो या तो मर गए हैं-उदास हैं, गंभीर हैं। ध्यान बहुत गंभीर लगता है, उदास लगता है, जिनके चेहरे लंबे हो गए हैं, जिन्होंने उत्साह, मस्ती, प्रफुल्लता, उत्सव सब खो दिया। यही तो ध्यान के गुणधर्म हैं। जो व्यक्ति वास्तव में ध्यानी है, वह खेलपूर्ण होगा। जीवन उसके लिए मस्ती है, एक लीला, एक खेल है। वह जीवन का परम आनंद लेता है। वह गंभीर नहीं होता, विश्रामपूर्ण होता है। जल्दीबाजी मत करो। बहुत बार जल्दीबाजी करने से ही देर हो जाती है। जब तुम्हारी प्यास जगे, तो धैर्य से प्रतीक्षा करो। जितनी गहन प्रतीक्षा होगी, उतनी जल्दी ही वह आएगा। तुमने बीज बो दिए, अब छाया में बैठे रहो और देखो क्या होता है! बीज टूटेगा, खिलेगा, लेकिन तुम प्रक्रिया को तेज नहीं कर सकते। क्या हर चीज के लिए समय नहीं चाहिए? तुम कार्य करो, लेकिन परिणाम परमात्मा पर छोड़ दो। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। विशेषतः सत्य की ओर उठाए गए कदम। परंतु कई बार अधैर्य उठता है, प्यास के साथ ही आता है अधैर्य, पर वह बाधा है। प्यास को बचा लो और अधैर्य को जाने दो। अधैर्य को प्यास के साथ मिलाओ मत। प्यास में उत्कंठा तो होती है, परंतु कोई संघर्ष नहीं होता। अधैर्य में संघर्ष होता है और कोई उत्कंठा नहीं होती।

अभीप्सा में प्रतीक्षा तो होती है, परंतु कोई मांग नहीं होती। अधैर्य में मांग होती है और कोई प्रतीक्षा नहीं होती। प्यास में तो मौन आंसू होते हैं। अधैर्य में बेचैन संघर्ष होता है। सत्य पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। वह तो समर्पण से पाया जाता है, संघर्ष से नहीं। उसे समग्र समर्पण से जीता जाता है। यही कारण है कि शिक्षित लोग चालाक हो जाते हैं, क्योंकि वे छोटे मार्ग खोजने में सक्षम होते हैं। यदि तुम न्यायोचित ढंग से धन कमाओ, तो तुम्हारा पूरा जीवन भी इसमें लग सकता है। लेकिन यदि तुम तस्करी से, जुए से या किसी और ढंग से -राजनेता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनकर धन कमा सको, तो सभी छोटे मार्ग तुम्हें उपलब्ध होंगे। शिक्षित व्यक्ति चालाक हो जाता है। वह बुद्धिमान नहीं बनता, बस चालाक हो जाता है। वह इतना चालाक हो जाता है कि बिना कुछ किए सब कुछ पा लेना चाहता है। ध्यान उन्हीं लोगों का घटता है, जो परिणामोन्मुख नहीं होते। ध्यान परिणामोन्मुख न होने की दशा है।

सही मार्ग का चुनाव करें

सूत्र

अहंकार परिणामोन्मुख है, मन सदा परिणाम के लिए लालायित रहता है। मन का कर्म में कोई रस नहीं होता। यदि कृत्य से गुजरे बिना ही मन परिणाम पा सके, तो वह छोटे मार्ग का ही चुनाव करेगा। मन को कर्म की ओर प्रेरित करें और जीवन में सही मार्ग का चुनाव करें।

दूसरा पहलू

'ह्यूमन वाइरोम प्रोग्राम' से मनुष्य के शरीर में मौजूद उन वायरसों का पता चलेगा, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।

मनुष्य के भीतर मौजूद वायरस की अनजानी दुनिया

हम अच्छे से जानते हैं कि वायरस हमें बीमार कर देते हैं। इन्फ्लूएंजा वायरस बिस्तर पकड़वा देता है और चेचक (माता) का वायरस तो जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वस्थ लोगों में ऐसे वायरस भी होते हैं, जो हमें बीमार नहीं करते। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे अंदर दसियों खरब वायरस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक अंश की पहचान हो पाई है। इस वर्ष पांच विश्वविद्यालय इन वायरसों की अभूतपूर्व खोज करने के लिए टीमें बना रहे हैं। ये टीमें हजारों प्रतिभागियों से लार, मल, रक्त, दूध और अन्य तरह के सैंपल एकत्रित करेंगी। करीब पांच वर्ष तक चलने वाली इस खोज को 'ह्यूमन वाइरोम प्रोग्राम' नाम दिया गया है और इस पर 17.1 करोड़ डॉलर खर्च आएगा। एकत्रित किए गए सैंपलों की जांच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सिस्टम की मदद से की जाएगी और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ह्यूमन वाइरोम हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक बुशमैन कहते हैं, 'मुझे लगता है कि यह हमारे पास अब तक मौजूद जानकारियों को नई दिशा देगा।' वैज्ञानिकों ने करीब सौ साल पहले फेज नाम के वायरस का पता लगाया था, जो मल के सैंपल में मिला था। फेज आंत के बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकता है। फेज मुंह, फेफड़ों और त्वचा में भी पाए गए। वैज्ञानिकों ने बाद में पता किया कि वायरस बिना किसी खास लक्षण के भी हमारी कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में नई आनुवंशिक अनुक्रमण विधियों से यह पता चला कि प्रत्येक ग्राम मल में अरबों फेज होते हैं। 1997 में, जापान में शोधकर्ताओं ने एक मरीज के रक्त का निरीक्षण करते हुए एनेलो वायरस की खोज की। बायोलॉजिस्ट डॉ. पारडीस सबेटी और उनकी टीम को उम्मीद है कि एआई 'ह्यूमन वाइरोम प्रोग्राम' को सफल बनाने में अहम उपकरण साबित होगा। इसके बाद शोधकर्ता यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वायरस हमारे शरीर के भीतर कर क्या रहे हैं। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि ये वायरस बैक्टीरिया को खत्म कर अपनी और प्रतियां बना रहे हैं। लेकिन हालिया प्रयोग के अनुसार, शरीर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया एक साझेदारीपूर्ण संबंध बनाते हैं और ये साझेदारी स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी हो सकती है। प्रयोग बताते हैं कि साइटेमेगालोवायरस हमें त्वचा कैंसर से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। हम अमूमन वायरस को लेकर जैसी सोच रखते हैं, यह उसके प्रतिकूल है।

कार्ल जिमर

वैज्ञानिकों ने करीब सौ साल पहले फेज वायरस का पता लगाया था, जो मल के सैंपल में मिला था। फेज आंत के बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकता है।

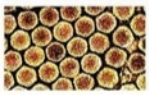

स्वस्थ लोगों में ऐसे वायरस भी होते हैं, जो हमें बीमार नहीं करते। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे अंदर दसियों खरब वायरस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक अंश की ही पहचान हो पाई है।

©The New York Times 2025

आंकड़े

रोजमर्रा के रोबोट

स्टेटिस्टा के सर्वेक्षण अनुसार, फ्रांस में सबसे ज्यादा लोग घरेलू रोबोट से मदद ले रहे हैं, जबकि अमेरिका भारत से भी पीछे है।

फ्रांस	14%
चीन	14%
भारत	13%
जर्मनी	13%
अमेरिका	12%

आंकड़े रोजमर्रा के घरेलू रोबोट उपयोग करने वाले देशों के, प्रतिशत में | स्रोत : Statista

अमृतनाथ जी की ख्याति सुनकर राजा माधव सिंह ने मकान और गांव भेंट करने की इच्छा जताई। अमृतनाथ जी बोले, उसे जरूरतमंद लोगों को भेंट कर दो।

भगवान की कृपा

अंतर्यात्रा
संकलित

अमृतनाथ जी महाराज का जन्म जयपुर के पिलाणी नामक गांव में हुआ था। जन्म के समय उनका शरीर छह माह के हृष्ट-पुष्ट बालक के समान बड़ा और बेहद आकर्षक था। पिता ने उनका नाम बचपन में यशराम रखा था। वह जब युवा हो गए, तब उनकी माता का देहांत हो गया, जिनके साथ वह जन्मसिद्ध योगी होते हुए भी बड़ा स्नेह संबंध रखते थे। माताजी के देहांत के बाद यशराम उसी वर्ष अपने घर से निकल पड़े और स्वामी चंपानाथ जी महाराज से संन्यास की दीक्षा ली और अपना नाम यशराम से बदलकर 'अमृतनाथ' रख लिया।

तदनंतर उन्होंने चौबीस वर्षों तक पर्वत-गुफाओं में निवास करके घोर तपस्या की। इस तपस्या से उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां सुलभ हो गईं। कुछ समय बाद अमृतनाथ जी के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। उनके पास हजारों रोगी, दुखिया आदि आया करते थे और वह किसी को निराश नहीं करते थे। उनके पास आने वाले हर इन्सान की समस्या का निदान हो जाता। अमृतनाथ जी लोगों से कहते, सब भगवान की कृपा है, मैं कुछ नहीं करता, वही सब ठीक करते हैं। स्वयं को भगवान की भक्ति में समर्पित कर दो। अमृतनाथ जी की ख्याति सुनकर राजा माधव सिंह ने उनकी सेवा में कुछ मकान और एक गांव भेंट करने की इच्छा जताई। काफी अनुनय-विनय करने पर भी उन्होंने राजा की भेंट स्वीकार नहीं की। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे जरूरतमंद लोगों को भेंट कर दो।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 17 अक्तूबर, 1965

भारत दबाव में हमलावर को रियायतें नहीं देगा

भारत दबाव के आगे झुक कर हमलावर को रियायतें नहीं देगा

संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर पर पाकिस्तान की दलीलों का उत्तर देते हुए भारत के प्रतिनिधि डॉ. जकारिया ने कहा कि भारत पर हमला करने वाले को रियायतें देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। भारत दबाव में रियायतें नहीं देगा।

महंगाई की मार और मरम्मत का अधिकार

मरम्मत के अधिकार के बिना उपभोक्ता आर्थिक बोझ उठाता है, तो पुराने उपकरणों को कबाड़ में डालने से पर्यावरण पर भी असर पड़ता है।

विवेक एस अग्रवाल | मुद्दा

उपभोक्तावादी युग में गौण होते उपभोक्ताओं पर कुछ सबसे बड़ी मार नित्य नई प्रकट होती यांत्रिक उपकरणों और संसाधनों से पड़ रही है। बीते वर्षों में पुरजोर तरीके से मरम्मत के अधिकार की बात विभिन्न स्तरों पर उठाई गई, लेकिन इस बाबत सरकार द्वारा एक पोर्टल की स्थापना तथा उसकी संपूर्ण संरचना के लिए कमेटी गठित करने से आगे कदम नहीं बढ़ पाए।

वर्तमान युग में, जहां हर वस्तु त्वरित बदलाव के सांचे में ढल रही है, वहीं निर्माताओं की भी अपेक्षा रहती है कि मॉडल में बदलाव या उन्नयन के नाम पर उपभोक्ता उसके नए उत्पाद को खरीदते रहें। इससे निर्माता का स्वार्थ तो सध जाता है, पर उपभोक्ता आर्थिक मायाजाल में फंस जाता है।

जब मरम्मत के अधिकार संबंधी चर्चाएं चल रही थीं, तो उसमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और कृषि उपकरणों को ही तरजीह दी गई, जबकि आमजन को प्रभावित करने वाले मेडिकल उपकरणों और मशीनरी को इस चर्चा से बाहर ही रखा गया। यह अलग बात है कि अभी सम्मिलित उपकरण व मशीनरी भी अपनी पूर्णता हासिल नहीं कर पाई। प्रचार-प्रसार के अभाव में उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा विकसित 'राइट टू रिपेयर' पोर्टल भी आमजन के चलन में नहीं आया है।

मरम्मत के अधिकार के बिना निर्माता के एकाधिकार के चंगुल में उपभोक्ता कहीं मशीन या उपकरण स्वयं क्रय करके फंस रहा है, तो मेडिकल जैसे क्षेत्र में निदान एवं उपचार हेतु मशीनों एवं उपकरण के बढ़ते उपयोग के कारण अनचाहे भी एकाधिकार वाली व्यवस्था का भार ढोता है। इसका एक पहलू यह भी है कि प्रथमतया तो संबंधित मशीनों के कलपुर्जे कहीं उपलब्ध ही नहीं होते और यदि हो भी जाएं, तो दूसरे से मरम्मत कराने पर उनसे जुड़ी हुई गारंटी-वारंटी भी समाप्त हो जाती है। यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि मशीन की बाहर मरम्मत का दंड भी क्रेता अस्पताल या निदान केंद्र को परोक्ष तौर पर चुकाना ही पड़ता है। यह ऐसा गंभीर विषय है, जिस पर न सिर्फ व्यापक चर्चा होनी चाहिए, बल्कि कानून के जरिये चिकित्सकीय उपकरणों को भी अन्यत्र मरम्मत के अधिकार के दायरे में लाया जाना चाहिए।

विडंबना यह है कि हर निर्माता नवीनता के नाम पर आंशिक, क्षणिक एवं कलात्मक बदलाव कर निरंतर नए उत्पाद को बाजार में ले आता है और आधुनिकतम इलाज के नाम पर उसे स्वीकार करना और अपनाना इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के लिए जरूरी हो जाता है। अन्यथा, वे स्वयं को बाजार की दौड़ से पीछे पाने लगते हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान में 3 टेस्ला एमआरआइ मशीन का प्रचलन है, जो 15 से 20 करोड़ रुपये की लागत की होती है और निर्माता कंपनी उसके रखरखाव हेतु लगभग 50 लाख रुपये प्रतिवर्ष का 10 वर्ष के लिए अनुबंध करती है। लेकिन इस बीच में ही इसके आंशिक उन्नयन का नया मॉडल आ जाता है और बाजार की दौड़ में रहने के लिए संस्थान को उसे खरीदना पड़ता है।

मरीज की भी अपेक्षा रहती है कि उसका निदान एवं उपचार आधुनिकतम मशीन से ही हो। वर्तमान युग में शनैः शनैः मरम्मत का स्थान परिवर्तन या नवीनता ने ले ली है। निर्माता नए मशीन-उपकरण को बाजार में लाने के साथ-साथ अपने ही पुराने उत्पाद को अप्रचलित करार देने लगता है तथा उसके कल पुर्जों को भी चलन से बाहर बता देता है। नतीजतन, चिकित्सकीय संस्थान कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए लंबी प्रतीक्षा के बजाय बदलाव करना पसंद करते हैं और पुरानी मशीन को कबाड़ में डाल देते हैं। यह न तो पर्यावरण सम्मत है और न ही मरीज के हित में, क्योंकि नई मशीन की लागत इलाज और निदान पर अतिरिक्त बोझ के रूप में दिखती है। इससे अनजान मरीज आधुनिकतम निदान एवं इलाज की प्रत्याशा में बढ़े हुए खर्च को चुपचाप सहन करता है। बीमित व्यक्ति के लिए तो यह प्रत्यक्ष बोझ नहीं होता, पर सामान्य लोग इसकी चपेट में आए बिना भी नहीं रहते।

बढ़ते चिकित्सा व्यय में मशीन और उपकरण पर हो रहे अनियंत्रित, निरंकुश तथा निरंतर खर्च की भी भूमिका है। इसके बहुत बड़े हिस्से पर नीतिगत रूप से मरम्मत के अधिकार को कायम करके तथा आमजन में जागृति पैदा कर अंकुश लगाया जा सकता है। मरम्मत का अधिकार लागू होने से खरीदारों को भी कम लागत पर बिना गारंटी खत्म किए ठीक कराने का विकल्प मिल जाएगा। इससे निर्माता कंपनियों को भी लाभ होगा, क्योंकि उनके द्वारा शिक्षित-प्रशिक्षित कुशल कारीगर जब कोने-कोने में कायम हो जाएंगे, तो उन्हें भी बड़ा बाजार मिलेगा। अधिक परिमाण में कारोबार होने से लागत में कमी आएगी और सामान्य नागरिक को सुलभ उपचार उचित दर पर मिल पाएगा।

दैनिक जागरण
अध्यात्म ही आत्मशक्ति से साक्षात्कार कराता है

सेहत का संदेश

प्रधानमंत्री ने सेहत के प्रति जागरूकता लाने और इस क्रम में मोटापे से लड़ने के लिए अपने-अपने क्षेत्र के दस जाने-माने लोगों को नामांकित कर यही रेखांकित किया कि इस समस्या की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने आनंद महिंद्रा, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनु भाकर, मीराबाई चानू, मोहनलाल, नंदन नीलेकणि, उमर अब्दुल्ला, आर. माधवन, श्रेया घोषाल, सुधा मूर्ति को नामांकित करते हुए यह अपेक्षा जताई कि ये सभी मोटापे के खिलाफ लड़ाई की अलख जगाने के साथ खाद्य तेल की खपत कम करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री ने समाज में असर रखने वाली इन हस्तियों से दस-दस और लोगों को इसी अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नामांकित करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री की यह पहल कुछ वैसी ही है, जैसी उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ करते समय की थी। इस पहल के भी अनुकूल परिणाम सामने आने चाहिए, लेकिन इसमें वांछित सफलता तभी संभव है, जब आम लोग यह समझेंगे कि सेहतमंद जीवनशैली अपनाने की आवश्यकता बढ़ गई है। आज की सुविधापूर्ण जीवनशैली मोटापा बढ़ाने का काम कर रही है। अब लोग उतना शारीरिक श्रम नहीं करते, जितना पहले अपनी सामान्य दिनचर्या के तहत किया करते थे। इसके अतिरिक्त खानपान की आदतें भी मोटापा बढ़ा रही हैं।

मोटापे को लेकर लोगों को सचेत होने की आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि वह अनेक बीमारियों का कारण बनता है। बीमार शरीर केवल कार्यक्षमता को कम करने का ही काम नहीं करता, बल्कि स्वास्थ्य पर खर्च भी बढ़ाता है। सेहतमंद लोग किसी भी देश के लिए एक बड़ी पूंजी होते हैं। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो लोग मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और वे अपना काम कहीं अधिक तत्परता एवं निपुणता से करते हैं। इसका लाभ केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज और देश को भी मिलता है। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने सेहतमंद जीवन शैली की जरूरत को समझा, लेकिन इसके लिए जागरूकता अभियान छेड़ने के साथ ही मिलावटी और दोयम दर्जे की खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए भी कुछ करना होगा। यह किसी से छिपा नहीं कि अपने देश में बड़े पैमाने पर मिलावटी और दोयम दर्जे की खाद्य सामग्री बनती एवं बिकती है। इसमें एक बड़ा हिस्सा उस खाद्य सामग्री का होता है, जो सड़क किनारे की दुकानों पर मिलती है। इस सामग्री में केवल खाद्य तेल की मात्रा ही अधिक नहीं होती, बल्कि वह मिलावटी भी होता है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी के चलते दोयम दर्जे की खाद्य सामग्री घरों में भी इस्तेमाल होती है। इनमें खाद्य तेल भी है। आज जब बाजार का खाना खाने का चलन बढ़ रहा है, तब सरकार को यह सुनिश्चित करना ही चाहिए कि उसकी शुद्धता से कोई समझौता न होने पाए।

सुविधाजनक पहल

हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए प्रवेश शुल्क (एंट्री टैक्स) भुगतान की सुविधा को व्यवस्थित करने के लिए सरकार की ओर से की जा रही पहल सराहनीय है। शुरुआती चरण में वाहन चालकों को प्रदेश के छह टोल बैरियर पर प्रवेश कर का भुगतान फास्टैग से करने की सुविधा मिलेगी। इसके बाद सभी 55 बैरियर पर इसे शुरू किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैरियर की नीलामी होने वाली है। इसमें सरकार की ओर से शर्त रखी जाएगी कि चयनित इकाइयों के सफल टोल पट्टेदारों को 45 दिन के भीतर फास्टैग आधारित प्रवेश कर प्रणाली का कार्यान्वयन करने की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। निश्चित तौर पर इससे वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी और कई लाभ होंगे। अक्सर देखा गया है कि टोल बैरियर पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इससे वाहन चालकों का समय भी बर्बाद होता है और जाम के कारण ईंधन भी खपता है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ता है। वास्तव में हम ईंधन संबंधी जरूरतें आयात के जरिये पूरी करते हैं। इस पर बहुत खर्च करना पड़ता है। हमारा पैसा विदेश चला जाता है। कई बार टोलकर्मियों पर मनमानी दरें वसूलने के आरोप भी लगते रहे हैं। फास्टैग से भुगतान होने से वाहनचालकों को सुविधा मिलेगी। उनके समय और ईंधन की बचत होगी और मनमाने दाम भी नहीं वसूले जा सकेंगे। वाहन अधिक देर तक बैरियर पर नहीं रुकेंगे, जिससे यातायात की समस्या का भी काफी हद तक समाधान हो सकेगा। जेब में नकदी रखने की चिंता भी नहीं रहेगी।

> प्रदेश के टोल बैरियर पर फास्टैग से भुगतान की सुविधा लोगों को राहत देगी

ठीक नहीं विदेशी रक्षा सामग्री पर निर्भरता

दिव्य कुमार सोती

अबकी बार विदेशी लड़ाकू विमान खरीदते हुए यह एक राष्ट्रीय संकल्प होना चाहिए कि भारत अंतिम बार ही कोई विदेशी लड़ाकू विमान खरीद रहा है

अवधेश राजपूत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान एफ-35 की भारत को बिक्री की पेशकश की। इसके बाद से देश में बहस छिड़ी हुई है कि भारत को ये विमान खरीदने चाहिए या नहीं। इसका एक कारण यह है कि अमेरिका की तरह रूस ने भी भारत को अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान सुखोई-57 को बेचने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में सुखोई-57 का भारत में रूस द्वारा निर्माण और उसके कलपुर्जों के निर्माण का काम भारतीय कंपनियों को दिया जाना भी शामिल है। रूस इस सौदे में भारत को पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की तकनीक भी हस्तांतरित करने को तैयार हो सकता है, जिसमें फाइटर जेट इंजन निर्माण से लेकर रडार तकनीकी भी शामिल होगी। विडंबना यह है कि भारत में बहस इस पर केंद्रित रहती है कि किस देश से कौन सा हथियार खरीदा जाए। जहां हम इस प्रश्न को लेकर उलझे हैं कि पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान अमेरिका से खरीदे जाएं या रूस से, वहीं चीन ने छठी पीढ़ी के स्वनिर्मित लड़ाकू विमान का परीक्षण शुरू कर दिया है। भारत चौथी पीढ़ी के स्वनिर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस की वायुसेना को अपेक्षित आपूर्ति ही नहीं कर पा रहा है। इसे लेकर बीते दिनों वायुसेना प्रमुख ने भी असंतुष्टि जाहिर की। अगर हम यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी दबाव मान लेते तो संभव है कि तेजस के लिए जरूरी अमेरिकी कंपनी जीई के इंजन मिल गए होते। वैसे तेजस भी पूरी तरह स्वदेशी नहीं है।

इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि रूस सैकड़ों प्रतिबंधों और दबावों के बावजूद तीन सालों से यूक्रेन युद्ध इसलिए जारी रख पा रहा है, क्योंकि वह हथियारों के निर्माण और ऊर्जा संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर है। यह क्षमता ही किसी देश को सही मायनों में संप्रभु महाशक्ति बनाती है। इस क्षमता का ही परिणाम है कि अमेरिका के नए सत्ताधीश यह बखूबी समझते हैं कि रूस जैसी आत्मनिर्भर शक्ति को निर्णायक रूप से हराया नहीं जा सकता और वे अब रूस से समझौते की बात कर रहे हैं। भारत विभिन्न देशों पर अपनी निर्भरता के चलते आज तक कोई युद्ध इतने समय तक चला ही नहीं पाया और युद्ध के मैदान में जीती बाजी भी हम विदेशी दबाव के चलते वार्ता की मेज पर हारते रहे हैं। 1971 का युद्ध गुलाम कश्मीर पर कोई निर्णायक फैसला लिए बिना जल्दबाजी में इसलिए समाप्त किया गया था, क्योंकि सोवियत नेता अमेरिका से एक सीमा से अधिक रार नहीं बढ़ाना चाहते थे और हम रक्षा और दूसरे मामलों में सोवियत संघ पर निर्भर थे। यही कारण है कि भारत के पहले सीडीएस रहे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत चाहते थे कि भारत अपने रक्षा उपकरण स्वयं ही बनाए और वे अगर विदेशी रक्षा उपकरणों से गुणवत्ता में थोड़े कमतर भी हों तो भी स्वदेशी उत्पादों को ही वरीयता दी जानी चाहिए। जनरल रावत का कहना था कि यदि कोई स्वदेशी रक्षा उत्पाद गुणवत्ता के 70 प्रतिशत मानक भी पूरे कर दे तो विदेशी साजोसामान के मुकाबले उसे वरीयता मिलनी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो देश का धन देश से बाहर नहीं जाता और बिना किसी दूसरे देश की नीतिगत प्राथमिकताओं का दबाव झेले ऐसे रक्षा उपकरणों का अनवरत उत्पादन किया जा सकता है।

जहां तक गुणवत्ता का प्रश्न है तो तकनीकी विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें असफलताओं से भी सीखने को मिलता है और समय के साथ खामियों को गहन अनुसंधान से दूर किया जा सकता है। चंद्रयान-2 की असफलता के बाद चंद्रयान-3 में किए गए सुधारों के चलते वह बेहद सफल रहा। गुणवत्ता में क्रमिक सुधार का चीन सबसे बड़ा उदाहरण है। चीन भी शुरुआती दिनों में हथियारों के लिए सोवियत संघ पर निर्भर था, परंतु उसने जो लड़ाकू विमान और युद्धक उपकरण एक बार सोवियत संघ से खरीदे, उनकी नकल कर वैसे ही उत्पाद स्वयं बनाने की कोशिश की। रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाए गए ये उत्पाद प्रारंभ में अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं थे, परंतु चीन निरंतर अनुसंधान में लगा रहा। चीनी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से अपने छात्रों को पढ़ने विश्व भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों में भेजा, जहां उन्होंने उच्च तकनीक से जुड़ा ज्ञान हासिल किया। बाद में विदेशी कंपनियों से भी ऊंचे पैकेज देकर उन्हें वापस चीन बुलाया ताकि वे अपने देश के लिए काम करें। सोवियत संघ ने भारत और चीन को मिग-21 विमान 1961-62 में लगभग एक ही समय पर बेचे थे। चीनी इंजीनियरों ने मिग-21 और सुखोई-15 के डिजाइन की नकल कर 1980 तक आते-आते अपना लड़ाकू विमान जे-8 बना डाला। 2017 में स्वनिर्मित पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जे-20 को चीन अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। इसके विपरीत 1984 में शुरू किए गए भारतीय हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के अंतर्गत तेजस विमान आज तक अपेक्षित संख्या में भारतीय वायुसेना को नहीं मिल सके हैं। यह स्थिति बहुत कुछ बताती है।

वायुसेना की आवश्यकताओं और भारत की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए अब सीमित मात्रा में ही विदेशी लड़ाकू विमानों की खरीद होनी चाहिए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो भी विदेशी लड़ाकू विमान खरीदा जाए, उसकी अधिकतर तकनीक का भी भारत को हस्तांतरण हो। अबकी बार विदेशी लड़ाकू विमान खरीदते हुए यह एक राष्ट्रीय संकल्प होना चाहिए कि भारत अंतिम बार ही कोई विदेशी लड़ाकू विमान खरीद रहा है। इसके बाद स्वयं ही अपनी सेनाओं की आवश्यकताओं के लिए उनका निर्माण किया जाएगा। यह एक राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक अनुसंधान के लिए जितने भी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता हो, सरकार को खुले मन से उन्हें मुहैया कराना चाहिए। साथ ही विदेशों में काम कर रहे उच्च कोटि के भारतीय इंजीनियरों को किसी भी कीमत पर वापस भारत में लाना चाहिए, जिससे भारत सही मायनों में एक आत्मनिर्भर महाशक्ति बन सके।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

नई शिक्षा नीति पर सस्ती राजनीति

प्रो. निरंजन कुमार

स्टालिन का यह दावा नितांत भ्रामक और भड़काऊ ही है कि तमिलनाडु पर हिंदी या संस्कृत थोपी जा रही है

प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो का कथन है, 'शिक्षा राजनीति की दासी नहीं, बल्कि सत्य और प्रगति का मार्गदर्शक होनी चाहिए।' दुर्भाग्य से ब्रिटिश शासन में मैकाले और स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और उनसे जुड़े शिक्षाविदों ने राजनीतिक स्वार्थों के लिए शिक्षा का दुरुपयोग किया, जिससे छात्रों, समाज और राष्ट्र को खासा नुकसान हुआ। वर्तमान में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लेकर तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र सरकार से की जा रही राजनीतिक रस्साकशी न केवल अवांछनीय है, बल्कि तमिलनाडु के छात्रों के हित में भी नहीं है। यह भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप भी नहीं है। वर्तमान विवाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कुछ और विशेष रूप से उसके भाषाई प्रविधानों को लेकर उठा है। स्टालिन एनईपी-के कई पहलुओं, जैसे त्रिभाषा सूत्र और कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का विरोध कर रहे हैं। त्रिभाषा सूत्र को लेकर उनका आरोप है कि यह तमिलनाडु पर हिंदी और संस्कृत को थोपता है और इससे तमिल भाषा और संस्कृति पर खतरा है। स्टालिन ने एनईपी को समग्र शिक्षा अभियान और पीएमश्री स्कूल से जोड़ने के लिए भी केंद्र सरकार की आलोचना की है और प्रधानमंत्री मोदी से समग्र शिक्षा अभियान के तहत धन जारी करने की अपील की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय संविधान के संघीय चरित्र का भी हवाला दिया है कि शिक्षा समवर्ती सूची में आती है और इसमें राज्यों को पूरी स्वायत्तता है।

तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ की कोशिश में स्टालिन सरकार इस तरह के दावे कर रही है। इस आशंका में कि द्रमुक इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ न उठा ले, तमिलनाडु की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी स्टालिन के स्वर में स्वर मिला रही हैं। मुद्दे को पूरी तरह से समझने के लिए एनईपी-2020 की निर्माण प्रक्रिया को जानना प्रासंगिक होगा। 21वीं सदी की सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हुई एनईपी-2020 को दुनिया भर में सराहा गया। तमिलनाडु सहित देश के चारों कोनों से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 676 जिलों के शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार एनईपी-2020 सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय है। एनईपी तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन स्वयं तमिल मूल के हैं। एनईपी तो भारतीय भाषाओं और बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। इसमें संविधान की आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाएं शामिल हैं। नया त्रिभाषा सूत्र पहले यानी 1968 और 1986 की त्रिभाषा नीतियों की तुलना में अधिक समावेशी और लचीला है। पहले की त्रिभाषा नीति में हिंदी-भाषी राज्यों में अंग्रेजी, हिंदी और एक अन्य भारतीय भाषा की पढ़ाई जाती थी, जबकि हिंदीतर राज्यों में अंग्रेजी, राज्य की क्षेत्रीय भाषा और हिंदी का प्रविधान था, लेकिन नई नीति में छात्र कोई भी दो भारतीय भाषाएं पढ़ सकते हैं। अब हिंदी या कोई भी भाषा विशेष अनिवार्य नहीं है यानी तमिलनाडु या किसी भी राज्य का छात्र तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, हिंदी, संस्कृत, या आठवीं अनुसूची की कोई भी भाषा पढ़ सकता है। इसलिए स्टालिन का यह दावा कि तमिलनाडु पर हिंदी या संस्कृत थोपी जा रही है, भ्रामक और भड़काऊ है।

नए त्रिभाषा सूत्र से छात्रों को अन्य भाषाओं और संस्कृतियों को समझने का अवसर मिलेगा। इससे तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के लोगों को व्यापार, व्यवसाय और अन्य क्रियाकलापों में आसानी होगी। संवैधानिक दृष्टिकोण से भी त्रिभाषा नीति भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप है, क्योंकि त्रिभाषा से उपजे बहुभाषावाद से लोगों में आपसी समझ एवं आत्मीयता बढ़ेगी। भाषाएं केवल संचार की माध्यम नहीं, साहित्य-सांस्कृतिक समझ को विकसित कर सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा भी देती हैं। शिक्षा समवर्ती सूची में है, लेकिन अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि राज्य और केंद्र के कानून में विरोधाभास हो, तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 257 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारें ऐसे कदम न उठाएं, जो केंद्र की नीतियों में अवरोध बनें। कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या मल्टीपल एंट्री-एग्जिट जैसी व्यवस्था तो सराहनीय और छात्रहित में हैं। इनका विरोध विशुद्ध राजनीति ही है। यदि भविष्योन्मुखी एनईपी-2020 तमिलनाडु में लागू नहीं होगी तो वहां के छात्र राष्ट्रीय और वैश्विक अवसरों से वंचित रह जाएंगे।

स्टालिन बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार तमिल भाषा और संस्कृति को कमजोर कर रही है, जबकि मोदी संभवतः पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने तमिल भाषा-संस्कृति को बढ़ावा देने का अधिकतम प्रयास किया है। तमिल कवि-दार्शनिक तिरुवल्लुवर के नाम पर विश्वभर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की योजना, तमिल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए तिरुक्कुरल और अनेक प्राचीन तमिल ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराकर उन्हें प्रसारित करना, वाराणसी में 'काशी-तमिल संगमम' के जरिये उत्तर भारत में तमिल भाषा-संस्कृति के प्रचार की दूरदर्शी पहल, तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर देश भर में भारतीय भाषा उत्सव मनाना या तमिल भाषा में विभिन्न अखिल भारतीय परीक्षाओं का आयोजन कराना, ये सभी कदम प्रधानमंत्री मोदी की तमिल भाषा-संस्कृति के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में वैल्यू एडिशन कोर्स कमेटी के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

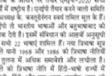

तमिलनाडु में भाषा पर भड़काऊ राजनीति। प्रेट्र

ऊर्जा

आशावाद का महत्व

आशावाद केवल एक मानसिक प्रवृत्ति नहीं, अपितु जीवन को गतिशीलता प्रदान करने वाला दार्शनिक दृष्टिकोण है। आशावाद व्यक्ति को निराशा, संदेह और हतोत्साह के अंधकार से निकालकर संभावनाओं के प्रकाश में खड़ा करता है। आशावादी व्यक्ति केवल परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से नहीं देखता, बल्कि प्रतिकूलताओं में भी संभावनाओं का बीज खोज लेता है। प्रख्यात अमेरिकी विचारक हेलेन केलर ने कहा है, 'आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। आशा और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है।'

मानव जीवन अनिश्चितताओं से परिपूर्ण है, जहां सफलता और असफलता, सुख और दुख, उत्थान और पतन का चक्र अनवरत चलता रहता है। ऐसे में यदि व्यक्ति नकारात्मकता के भार से ग्रस्त हो जाए, तो उसकी चेतना निष्क्रिय हो जाती है और वह पराजय को ही अंतिम सत्य मान बैठता है। इसके विपरीत, आशावाद व्यक्ति को हर कठिनाई में एक नया मार्ग दिखाता है, जिससे वह अपने ध्येय की ओर निरंतर अग्रसर रह सकता है। महात्मा गांधी ने कहा है, 'आशावान व्यक्ति हर कठिनाई में अवसर देखता है।' आधुनिक मनोविज्ञान भी यह सिद्ध कर चुका है कि आशावादी व्यक्ति अधिक आत्मविश्वासी, सृजनशील और मानसिक रूप से सशक्त होते हैं। वे जीवन में आने वाली चुनौतियों को अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं और निरंतर नवाचार की ओर अग्रसर रहते हैं। आशावाद न केवल व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। जीवन में सतत प्रेरणा, आत्मबल और उत्साह बनाए रखने हेतु आशावाद ही सबसे बड़ा संबल है। आशावाद के महत्व पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने यथार्थ ही कहा है, 'हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। आशा ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है।'

नृपेंद्र अभिषेक नृप

स्वच्छ नदियों पर निर्भर हमारा अस्तित्व

रंजना मिश्रा

> यमुना नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक और घरेलू कचरे का सीधे उसमें बहाया जाना है

यमुना नदी न केवल दिल्ली के लिए, बल्कि आस-पास के क्षेत्रों के लिए भी जीवन रेखा के समान है। हालांकि पिछले कुछ दशकों से यमुना नदी प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। इसका पानी न केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। यमुना नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक और घरेलू कचरे का सीधे नदी में बहाया जाना है। यमुना की सफाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो न केवल प्रदूषण को कम करने पर ध्यान केंद्रित करे, बल्कि नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को भी पुनर्स्थापित करे।

इसके लिए हाल में दिल्ली सरकार ने एक बहु-स्तरीय रणनीति अपनाई है। इसमें सबसे पहले यमुना नदी में वर्षों से जमा कचरा, गाद और गंदगी को हटाया जाना शामिल है। यह कार्य नदी के प्रवाह को बेहतर बनाने और प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करेगा। इसके लिए आधुनिक मशीनों और तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सफाई प्रक्रिया प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल हो। दूसरी रणनीति है, प्रमुख नालों की सफाई करना। यमुना नदी में प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत नजफगढ़, सप्लीमेंट्री और अन्य प्रमुख नाले हैं। इनमें औद्योगिक और घरेलू कचरा बहकर नदी में मिलता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए इन नालों की सफाई भी यमुना की सफाई के लिए महत्वपूर्ण कदम है। तीसरी रणनीति के तहत, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की निगरानी की जाएगी। दिल्ली में कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जो सीवेज को साफ करके नदी में छोड़ने के लिए बनाए गए हैं। इन प्लांटों की कार्यप्रणाली की निगरानी करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही तरीके से काम कर रहे हैं। यदि एसटीपी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो वे नदी में प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। औद्योगिक इकाइयां भी यमुना नदी में प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत हैं। कई औद्योगिक इकाइयां अपने कचरे को सीधे नदी में छोड़ देती हैं, जिससे नदी का पानी दूषित हो जाता है। इसलिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को औद्योगिक इकाइयों द्वारा नालों में डाले जाने वाले कचरे पर कड़ी निगरानी रखनी होगी।

दिल्ली सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को लगभग तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यह एक चुनौतीपूर्ण समय सीमा है, लेकिन यदि सभी हितधारक मिलकर काम करते हैं और योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यदि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और सही दिशा में प्रयास करें, तो यमुना नदी को फिर से साफ बनाया जा सकता है। यदि नदी साफ होगी तो लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ पानी मिलेगा, जिससे बीमारियों का खतरा कम होगा।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

सनातन विरोधियों को जवाब जरूरी

'अनर्गल टिप्पणियों का जवाब' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी में प्रधानमंत्री के संबोधन के बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, जो बातें उन्होंने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में मेडिकल कालेज की नींव रखते हुए कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ को निशाना बनाने वाले विपक्षी नेताओं के बयान सनातन में आस्था रखने वालों पर चोट करने के समान हैं। याद रहे कि कुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने इसे मृत्यु कुंभ और लालू यादव ने फालतू करार दिया था। हिंदू प्रतीकों पर विषाक्त टिप्पणियों का विष बढ़ता जा रहा है। यह सनातनियों की एकजुटता नहीं होने का परिणाम है। अन्यथा अन्य पंथ-मजहबों के प्रतीकों पर ऐसे बयान नहीं दिए जाते। यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। हिंदू त्योहारों पर विषाक्त टिप्पणी से न केवल सनातनियों की भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी कमजोर करता है। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करनी चाहिए और ऐसे बयानों का विरोध करना चाहिए जो हमारी भावनाओं को आहत करते हैं। इस मुद्दे पर हमें एकजुट होना चाहिए और अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमें अपने नेताओं से अपेक्षा करनी चाहिए कि वे ऐसे बयानों का विरोध करें और हमारी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करें। इसके अलावा, हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव लाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जान सकें और उसकी रक्षा कर सकें। हमें समाज में भी जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि लोग ऐसे बयानों का विरोध कर सकें। सनातन विरोधियों को जवाब देना जरूरी हो गया है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम(मप्र)

डबल इंजन सरकार से उम्मीद

रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट कर दी है कि वह बहुत सोच समझकर फैसले लेती है। वर्ष 2017 में जब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए थे, तब भाजपा वहां मुख्यमंत्री पद के लिए जयराम ठाकुर को सामने लाई थी, जबकि जयराम ठाकुर हिमाचल के लिए भाजपा का कोई खास चेहरा न थे। किसी भी राजनीति दल का उचित नेतृत्व ही उस दल की नैया हर चुनाव में पार लगाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का कद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रेखा गुप्ता भाजपा का कोई खास चेहरा नहीं थीं, लेकिन भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर यह संदेश दिया कि भाजपा किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर अपने विरोधियों की उस आवाज पर भी पूर्ण विराम लगा दिया जो यह कहते थे कि भाजपा महिलाओं को मुख्यमंत्री पद नहीं देती, क्योंकि जिन भी राज्यों में भाजपा सरकार है वहां अब तक पार्टी ने किसी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। अब दिल्ली में डबल इंजन सरकार तैयार है। यह देखना है कि यह डबल इंजन की सरकार दिल्ली के इतने अच्छे दिन लाती है और प्रदूषण, दूषित पानी, स्वच्छता और अन्य समस्याओं को कितना दूर कर पाती है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सनातन को बदनाम न करें

कुछ राजनेता अपने वोट बैंक की खातिर सनातन धर्म को लेकर कभी-कभी बेतुका बयान देते हैं। कोई भी धर्म हमें नफरत, वैर विरोध या दूसरे धर्मों की निंदा करने की शिक्षा नहीं देता है। लेकिन अफसोस कुछ लोग धर्म का असल मतलब नहीं समझते। दूसरे धर्मों के साथ नफरत करते हैं। यही काम मुगलों ने करके हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त किया। आज भी ऐसे कुछ धर्म के ठेकेदारों और अन्य लोगों की कमी नहीं है जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, दूसरे धर्मों के प्रति निंदा भरी बातें करते हैं। हिंदू धर्म के लोग फिर भी किसी धर्म की बुराई नहीं करते हैं। सनातन धर्म के लोग तो सूर्य, पानी, अग्नि, हवा, धरती सबकी पूजा करते हैं, क्योंकि यह सभी प्राणी जाति का कल्याण करते हैं, फिर सनातन को लेकर कुछ लोगों में नफरत क्यों?

raju09023693142@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHI/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

7.25 लाख से अधिक भारत के लोग अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं, प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार। इस मामले में भारत मेक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद तीसरे स्थान पर है।

आजकल

भारत-अमेरिका संबंध और ट्रंप

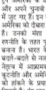

डा. सुशील कुमार सिंह
निदेशक, वाईएस रिसर्च फाउंडेशन आफ पालिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन

अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर काबिज होते ही अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख अमेरिका को दोबारा महान बनाना शामिल है। उनकी मंशा नई कूटनीति तथा रणनीति के जरिये पूरी दुनिया पर दबाव बनाकर अपने हित साधना है। ट्रंप के नेतृत्व में आक्रामकता, लेनदेन संबंधी कूटनीति और अमेरिकी प्रभुत्व से दुनिया को हांकने के प्रयास की झलक साफ दिखती है। भारत के मामले में भी ट्रंप बदले-बदले से नजर आ रहे हैं

अपने बयानों से भारत के समक्ष हर दिन नई चुनौती पेश कर रहे डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर काबिज होते ही निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं और अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। इन वादों में सबसे प्रमुख अमेरिका को दोबारा महान बनाना शामिल है। उनकी मंशा नई कूटनीति तथा रणनीति के तहत पूरी दुनिया पर दबाव बनाना है। भारत के मामले में भी ट्रंप बदले-बदले से नजर आ रहे हैं। ट्रंप के नेतृत्व में आक्रामकता, लेनदेन संबंधी कूटनीति और अमेरिकी प्रभुत्व से दुनिया को हांकने के प्रयास की झलक साफ दिखती है। ट्रंप जब 2017 में पहली बार सत्ता संभाले थे तब सप्ताह भर के भीतर सात मुस्लिम बाहुल्य देश के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया, यमन, सूडान और सोमालिया शामिल थे। अब दूसरी पारी में अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों को बेड़ियों के साथ उनके देश वापस भेज रहे हैं, जिनमें भारत के नागरिक भी शामिल हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के विश्लेषण के अनुसार, भारत के सात लाख पच्चीस हजार से अधिक लोग अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं। इस मामले में भारत मेक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद तीसरे स्थान पर है। एच-1बी वीजा के मामले में भी भारतीय अमेरिका में असमंजस की स्थिति में हैं। अमेरिका में पैदा ऐसे लोगों के बच्चों की नागरिकता भी सवालों में है।

वैसे अमेरिका हमेशा से ही 'अमेरिका प्रथम' की नीति पर रहा है। उसकी नीति स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की रही है। इसके लिए वह हमेशा स्वहित को तरजीह देता रहा है। महज 33 करोड़ की जनसंख्या वाला यह देश 20 लाख करोड़ डालर से अधिक की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जबकि चीन 16 लाख करोड़ डालर के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या है, मगर अभी अर्थव्यवस्था मात्र चार लाख करोड़ डालर के आसपास ही है। इन दिनों ट्रंप की कूटनीति के प्रभाव से यूरोपीय संघ से लेकर कनाडा, मेक्सिको से चीन तक कोई भी देश अछूता नहीं है। यहां तक कि यूरोपीय राष्ट्र जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के गठबंधन की आधारशिला थे, वे भी ट्रंप के निशाने पर हैं। अमेरिकी की नीति में आया यह बदलाव उसके सहयोगियों और विरोधियों को अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि ट्रंप गठबंधनों और राजनयिक मानदंडों से ऊपर अमेरिकी हितों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। फिलहाल ट्रंप और मोदी में क्या कुछ समान है इसकी पड़ताल भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम वर्षों पहले ही चला चुके हैं, जबकि ट्रंप भी अमेरिका में निवेश की चाहत रखते हैं। ट्रंप जहां करों में कटौती और नियमों को कम करके सरकारी दक्षता बढ़ाने की इच्छा से युक्त हैं वहीं मोदी न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम शासन की नीति पर चल रहे हैं। एनआरसी के माध्यम से जहां मोदी सरकार अपने यहां अवैध प्रवास कर रहे लोगों के लिए एक सख्त नियम बनाने पर विचार कर रही है वहीं डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में कदम उठा चुके हैं। ट्रंप अमेरिका को महान बनाने की कवायद में हैं, जबकि मोदी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की कल्पना से भरे हैं। खास यह भी है कि अमेरिका भारत को एक वैश्विक शक्ति और मजबूत रणनीतिक एवं रक्षा भागीदार के रूप में उभारने के साथ हिंद महासागर की सुरक्षा के मामले में भी भारत के प्रति अच्छी दृष्टि रखता है। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप कई मामलों में भारत के प्रति कड़ा और सख्त रवैया अपना रहे हैं।

जो ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भारत के प्रति नरम और चीन के प्रति सख्त थे, अब सबको एक ही नजर से देख रहे हैं। इसके चलते संरक्षणवादी नीतियों और वैश्विक व्यापार में सख्ती का सहारा लेते दिख रहे हैं। ट्रंप की नीतियों से वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद का चलन बढ़ सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका उन देशों पर टैरिफ लगाएगा, जो व्यापार में अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने उच्च टैरिफ वाले देशों के रूप में चीन, भारत और ब्राजील का नाम लिया है। ये सभी देश ब्रिक्स समूह में शामिल हैं। वह धमकी भी दे रहे हैं कि ब्रिक्स देश नई मुद्रा को लेकर कोई कदम उठाते हैं और डालर का उपयोग कम करते हैं तो इसमें शामिल सभी देशों पर टैरिफ लगाएंगे। अच्छी बात है कि भारत इन सब पर कूटनीतिक चुप्पी साधे हुए है। अभी इसकी आवश्यकता भी है। समय आने पर रणनीतिक कदम उठाने चाहिए।

हमारे वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो जनवरी 2025 में अमेरिका को भारत का निर्यात सालाना आधार पर 39 फीसद बढ़कर लगभग साढ़े आठ अरब डालर हो गया, जबकि आयात लगभग 34 फीसद बढ़कर साढ़े तीन अरब डालर पार कर गया। वित्त वर्ष 2023-2024 में दोनों देशों के बीच लगभग 120 अरब डालर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों ने पांच सौ अरब डालर के दीर्घपक्ष व्यापार समझौते की ओर बढ़ने पर सहमति जताई है।

ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा हो चुकी है। फिलहाल भारत और अमेरिका की दोस्ती की कीमत से ट्रंप पूरी तरह भिज्ञ हैं। और भारत भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि अमेरिका उसके लिए क्या मायने रखता है। अंततः भविष्य में यह भी देखना होगा कि जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा, इजरायल-फलस्तीन, ईरान एवं रूस-यूक्रेन युद्ध समेत चीन तथा अन्य देशों एवं मुद्दों के प्रति ट्रंप का क्या रवैया रहता है?

भारतीय चुनावों में अमेरिकी धन का हस्तक्षेप

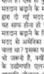

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

पूंजीवादी देश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आर्थिक मदद बेवजह नहीं होती? इनमें विकासशील देशों में अपने हित साधने का मकसद प्रच्छन्न रहता है। ऐसा ही कुछ उद्देश्य भारत में मतदान बढ़ाने के मकसद से अमेरिकी द्वारा दी गई मदद में अंतर्निहित है। यह साफ होना ही चाहिए कि भारत में मतदान बढ़ाने के लिए दी गई आर्थिक मदद से अमेरिका को क्या लाभ होने वाला था? इसका पर्दाफाश होना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि पहले अमेरिका के उद्योगपति एलन मस्क और फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देकर बताया है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने यह राशि भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए दी थी। यानी भारत में नरेन्द्र मोदी की सत्ता के बजाय किसी और की सत्ता चुनी जाए। 2.1 करोड़ डालर की यह वित्तीय मदद अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएड) द्वारा देश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर दी गई थी। अब इस अनुदान पर ट्रंप ने रोक लगा दी है। ट्रंप ने इस राशि को घूस कहा है। अनेक विदेशी एजेंसियां और एनजीओ देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्त्री-सशक्तीकरण, गरीबी-उन्मूलन, पर्यावरण और विकास के नाम पर आर्थिक सहायता देते रहते हैं, जिससे उनके व्यावसायिक एवं धार्मिक हित भी सधते रहें। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में कानून बनाकर इसे रोकने के प्रयास किए हैं, ताकि देश विरोधी गतिविधियां चलाने के मकसद से विदेशी धन नहीं आने पाए। कोई विदेशी आर्थिक मदद मिले भी तो वह भारत सरकार के माध्यम से आए।

माना जा रहा है कि भारत में आई यह धनराशि 4000 करोड़ रुपये की उस अंतरराष्ट्रीय निधि का हिस्सा थी, जिसे कंसोर्टियम फार इलेक्शंस एंड पालिटिकल प्रोसेस स्टेंथनिंग (सीईपीपीएस) नाम की संस्था ने जारी किया था। सीईपीपीएस ने इसे तीन स्वयंसेवी संगठनों को दिया था। इनमें से आइएफईएस एनजीओ चुनाव से जुड़ी शिक्षा एवं जागरूकता के लिए मुहिम चलाता है। एनडीआइ एनजीओ संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूती देने का अभियान चलाता है और आइआरआइ संगठन चुनाव एवं अन्य संस्थाओं में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने यह माना है कि यूएसएड की ओर से वित्त पोषित एक अमेरिकी संस्था से निर्वाचन आयोग का समझौता हुआ था, लेकिन किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं ली गई थी। अतः सवाल उठता है कि फिर समझौता किस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हुआ था? तय है, भारत सरकार इस वित्तीय मदद की जांच करती है तो परत दर परत कई रहस्य उजागर होंगे। भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया किसी भी प्रकार का विदेशी हस्तक्षेप देश विरोधी हरकत है। यह मदद 2012 से शुरू हुई थी। उस समय कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए की केंद्र में सरकार थी और डा. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे।

यह सच है कि पश्चिमी देश भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार, महिला कल्याण, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, एड्स और कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए उदारता से कई एनजीओ को अनुदान देते हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी कुटिल मंशा भी छिपी होती है। इनके जरिये इन देशों में वे पर्यावरण संरक्षण एवं वन विकास के नाम पर विकास कार्यों में बाधा पैदा करने का काम करते हैं। ज्यादातर एनजीओ इसके लिए न्यायालयों में जनहित याचिकाएं लगाकर सरकार के फैसलों में अड़ंगा लगाते हैं। अब चुनावों में मतदान बढ़ाने के नाम पर हस्तक्षेप करने से यह पता चलता है कि भारत की स्वायत्त संस्थाओं को प्रभावित करने में भी वे लगे हुए हैं।

खरी-खरी

वीआइपी वही जो भीड़ में न जाए

डा. प्रदीप मिश्र

भीड़ को भारी भरकम बनाने के लिए इसके आगे भाड़ लगाना पड़ता है। भाड़ के लगते ही भीड़ का वजन बढ़ जाता है। मतलब भीड़ जब भाड़ में जाती है, तब वह विशाल जनसमूह हो जाती है। आजकल भारतीय रेल के डिब्बों को भी भाड़ कहा जा रहा है। भीड़ वही जो भाड़ मन भाए। जो तो कहिए माल गाड़ियों के पास जीवित लोगों के लिए फुरसत नहीं है, वरना भीड़ उसमें भी भर जाने को तैयार है।

भीड़ नहाने भी जाती है। उसका मानना है कि नहाने से पाप धुल जाते हैं। मोक्ष भी मिलता है। मोक्ष सबको नहीं मिलता, इसलिए ज्यादातर लोग अपने पैरों पर चलकर घर वापस आ जाते हैं। दरवाजे पर उनके मोक्ष और संपत्ति की कामना कर रहे लोग कहते हैं, 'लो इस बार भी बाबूजी को मोक्ष नहीं मिला। अब और झेलो इन्हें अगले बारह साल तक।'

भीड़ भगदड़ की जननी होती है। आचार्यवर बताते हैं कि भीड़ में मची भगदड़ की वजह से जिन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, वे सीधे बैकुंठ धाम जाते हैं। जिन्हें बैकुंठ जाने का सौभाग्य नहीं मिलता वे आचार्यों की निंदा करते हैं। वीआइपी नहाने में भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। कहावत में को काको गोसाई? यानी जीवन में सभी एक समान हैं। वैसे तो जनता जनार्दन है, लेकिन स्नान प्राइवेट मामला है। वीआइपी वही जो भीड़ में न जाए। प्राइवेट घाट में नहाए और चार्टर जहाज से उड़ जाए। भीड़ कारों, बसों, ट्रकों, ट्रैक्टरों आदि में बैठकर नहाने जाती है। ऐसे में वाहनों की तादाद बढ़ जाती है। सड़क सकरी पड़ने लगती है। इन वाहनों के पास, क्योंकि उड़ने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए आकाश की जगह धरती पर जाम लगता है। जाम की तस्वीरें और वीडियो टीवी के पर्दे पर जाम लगा देते हैं। जाम को आम करता संकटदाता कहता है, 'यह जाम, न भूतो न भविष्यति वाला है।' इस बहाने वह गारंटी से बताता है कि उसे मालूम है कि 144 साल बाद लगने वाले कुंभ में भी ऐसा जाम नहीं लगेगा।

जनता, डुबकी से कुछ भी कम में मानने को तैयार नहीं है। मोक्ष नहीं मिला तो नहाने के लिए पवित्र-जल तो मिलेगा ही।

पोस्ट

भारत के खिलाफ पाकिस्तान की गेंदबाजी निस्तेज दिखी। विराट कोहली अपने रंग में आए। पाकिस्तानी क्रिकेट की गिरावट उनके देश की दयनीय हालत की ही तस्वीर पेश करती है। कभी क्रिकेट में बहुत आगे रहा पाकिस्तान अब बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जैसे देशों की श्रेणी में आ गया है।
सुशील दोषी@RealSushilDoshi

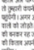

अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बहुत सीमित हो गया है, लेकिन जब भी उनके साथ मुकाबला होता है तो वह भारतीय क्रिकेट के उत्थान और पाकिस्तानी क्रिकेट के पतन को भी रेखांकित करता है। क्रिकेट का प्रारूप जितना बड़ा होता है, दोनों देशों के बीच अंतर की खाई भी उतनी ही चौड़ी दिखती है।
संजय मांजरेकर@sanjaymanjrekar

डेविड ओगिल्वी ने लिखा है कि अपने से बेहतर और योग्य लोगों की भर्ती करो तो तुम्हारी कंपनी सफलता के शीर्ष पर पहुंचेगी। अगर अपने से कमतर योग्यता वालों को जोड़ते हो तो कंपनी दोयम दर्जे की बनकर रह जाएगी। थरूर को ओगिल्वी की किताब अपनी पार्टी को भेंट करनी चाहिए।
सुहेल सेठ@Suhelseth

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या भाजपा सरकार दिल्ली को शहरी विकास के उदाहरण के रूप में स्थापित कर सकती है?

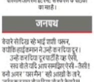

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या क्रिकेट में पाकिस्तान भारत के प्रबल प्रतिद्वंद्वी का दर्जा खो चुका है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बेचारे से दिख रहे भाई शशी थरूर,
क्योंकि हाईकमान ने उन्हें कर दिया दूर।
उन्हें कर दिया दूर पार्टी है यह ऐसी,
सच बोले यदि आप समझिए ऐसी-तैसी!
बनो अगर 'यसमैन' रहो आंखों के तारे,
तुरंत कर सच बोल दिया तो बने बेचारे!!

- ओमप्रकाश तिवारी

बंगाल डायरी

महाकुंभ पर टिप्पणी के बाद ब्राह्मण वाला दांव

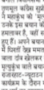

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

एक ओर प्रयागराज के संगम में देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालु पुण्य डुबकी लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने महाकुंभ को 'मृत्युकुंभ' कह दिया। उनके इस बयान को लेकर भाजपा जहां हमलावर है, वहीं साधु-संत भी भड़के हुए हैं। अपने बयान को लेकर विवादों में घिरीं देख ममता हिंदुत्व और ब्राह्मण वाला दांव खेलकर सफाई दे रही हैं। मृत्युकुंभ वाले बयान के दो दिन बाद राजरहाट-न्यूटाउन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ममता ने कहा-'मैं हर धर्म का सम्मान करती हूं।' उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा-'कौन कहता है कि मैं अपने धर्म का सम्मान नहीं करती? ध्यान रहना चाहिए कि धर्म एक व्यक्ति से जुड़ा होता है, लेकिन उत्सव सबके लिए होते हैं। हमारे देश में कई राज्य हैं और हर राज्य में अलग भाषा, शिक्षा, संस्कृति और आस्था हैं। हम हर संस्कृति का सम्मान करते हैं, इसीलिए विविधता में एकता हमारा दर्शन है, हमारी विचारधारा है।'

मृत्युकुंभ वाली टिप्पणी पर ममता ने सफाई दी कि वह एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार से हैं और उन्होंने अपने पिता से चंडीपाठ सीखा है। वह यह भी याद दिलाना नहीं भूलीं कि पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में जगन्नाथ मंदिर, कोलकाता में कालीघाट और दक्षिणेश्वर में काली मंदिर जाने के लिए स्काईवाक का निर्माण उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से कराए हैं। महाकुंभ को मृत्युकुंभ कहने के बाद ममता जिस तरह से खुद को हिंदू और ब्राह्मण बता रही हैं, महाकुंभ और गंगा मां का सम्मान करने की बातें कह रही हैं, वह 'डैमेज कंट्रोल' जैसी लग रही हैं। ममता काफी अनुभवी नेता हैं। उन्हें पता है कि मृत्युकुंभ वाली उनकी टिप्पणी उनके लिए गले का फांस बन सकती है, इसलिए वह हिंदू और ब्राह्मण वाली बातें कहकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ममता जिस तरह से 'जय श्रीराम' के नारे के खिलाफ गुस्सा हुई थीं, उसका उन्हें परिणाम भुगतना पड़ा था।

हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी रणनीति बदली और चुनाव प्रचार के दौरान मंदिरों के दौरे से लेकर चुनावी सभाओं में चंडीपाठ करना शुरू कर दिया, क्योंकि ममता जान चुकी हैं कि बंगाल का मुस्लिम वोट उनके अलावा कहीं और नहीं जाने वाला है। ममता ने 2021 से ही प्रतिस्पर्धी और सफ्ट हिंदुत्व को अपना रखा है, ताकि बहुसंख्यक समुदाय में हिंदुत्व समर्थक वोटरों को भाजपा की ओर जाने से रोका जा सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बंगाल में करीब 57 प्रतिशत और तृणमूल को केवल 32 प्रतिशत हिंदू वोट मिले थे। इसके बाद ममता ने अपनी रणनीति बदल ली। भाजपा को अधिक हिंदू वोट पाने से रोकने के प्रयास में उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए, जिससे वह बचा करती थीं। मसलन चुनाव के दौरान मंदिरों में जाना, इमाम एवं मुअज्जिनों के बाद हिंदू पुजारियों को मासिक भत्ता देना। 43,000 से अधिक दुर्गापूजा समितियों एवं क्लबों को प्रतिवर्ष नकदी, सरकारी प्रचार की होर्डिंग लगाने के लिए एक लाख से अधिक रुपये का अनुदान देना, दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन आदि प्रमुख हैं। यही नहीं, ममता सरकारी खर्च पर पुरी की तरह दीघा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करा रही हैं। इसी का असर रहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल को 39 प्रतिशत हिंदू वोट मिला और वह 211 सीटें जीत गईं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ममता को काफी फायदा हुआ। अब जबकि आगामी वर्ष बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है तो उनके लिए मुस्लिमों के साथ-साथ हिंदू वोट भी अहम है। इसीलिए मृत्युकुंभ की बातें कहने के बाद उन्होंने खुद को हिंदू धर्म की बड़ी हिमायती होने का दावा करना भी शुरू कर दिया है।

दूसरी तरफ भाजपा इस मुद्दे को यूं ही जाने देने के पक्ष में नहीं है। यही वजह रही कि पिछले दिनों विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने भाजपा विधायकों के साथ विधानसभा परिसर से लेकर राजभवन तक विरोध-प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी सड़क पर उतरे थे। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और अन्य राज्यों के भाजपा नेताओं ने एक साथ हमला बोला था। उसके बाद शुक्रवार को सुवेंदु ने संगम में जाकर डुबकी लगाई और कहा कि यह मृत्युकुंभ नहीं, बल्कि अमृतकुंभ है। बंगाल से भी लाखों लोग महाकुंभ में जा चुके हैं। ऐसे में प्रश्न उठ रहा है कि ममता ने मृत्युकुंभ वाला बयान किसे खुश करने के लिए दिया? इस मुद्दे के साथ-साथ राज्य के कई क्षेत्रों में सरस्वती पूजा में बाधा उत्पन्न करने के मामले को आगामी विधानसभा चुनाव तक भाजपा जीवित रख पाती है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी।

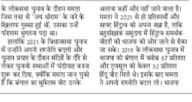

सीएम ममता बनर्जी के मृत्युकुंभ वाले बयान के खिलाफ प्रदर्शन करते भाजपा विधायक। फाइल

महाकुंभ

स्व जागरण का उत्प्रेरक

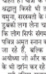

घनश्याम शाही
क्षेत्रीय संगठन मंत्री, पूर्वी उत्तर प्रदेश, एबीवीपी

भारत की एकात्मता, इसकी संगठन शक्ति, इसके समावेशी, सहभाव और सामंजस्य का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा महाकुंभ

प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ पर्व समापन की ओर है। हालांकि अभी भी सड़क हो, रेल हो या हवाई ऐसा लग रहा है कि सभी मार्ग प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं। यात्रा के कष्टों को सहते हुए श्रद्धालु किसी भी तरह पहुंचकर गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगा लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ संगम में कल्पवास और पवित्र अमृत स्नान करके ही वापस लौट जा रहे हैं, बल्कि श्रद्धालु साथ-साथ अयोध्या जी और काशी विश्वनाथ धाम के भी दर्शन कर रहे हैं।

पूरी दुनिया सनातन धर्म के इस पर्व को देखकर अचंभित है। पूरा विश्व बस एक प्रश्न पूछ रहा है कि हर 12 साल बाद प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और शिप्रा नदियों के किनारे आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में ऐसी क्या बात है कि दूर-दूर से श्रद्धालु बिना किसी बुलावे के खिंचे चले आते हैं? दरअसल हमारे भारतवर्ष की मिट्टी उत्सवधर्मी है। जीवन के चार लक्ष्यों- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने के लिए हम पर्व, त्योहार, उत्सवों का सहारा लेते हैं। इसीलिए हमें कोई कार्य बोझ नहीं लगता। जीवन को ध्येय मानकर कार्य करने की हमारी सदियों पुरानी परंपरा और संस्कृति रही है। इसी कारण राष्ट्रीय महत्व के सभी अवसरों पर किसी को आदेश देने या फिर बहुत व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सभी उसे अपनी जिम्मेदारी मान स्वतः निभाते हैं। इसीलिए इन कामों में अनुशासन अपने-आप आ जाता है। यही भारतीय मन है। इसमें जाति-पंथ का भेदभाव नहीं, अपितु वसुधैव कुटुंबकम् की भावना है। महाकुंभ इस बात का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। कौन बता सकता है कि संगम में स्नान करने वालों में किस जाति के कितने लोग थे? यह महाकुंभ समाज में वैमनस्य पैदा करने वाले उन लोगों को जवाब है, जो सनातनियों को जातियों में बांटकर कमजोर करने की साजिश में दिन-रात एक किए हुए हैं। हमारे देश को ऐसी ही उत्सवी एकता की जरूरत है।

महाकुंभ दिखाता है कि हिंदू अब जागृत हो रहे हैं। सदियों की गुलामी और हिंसा से भारतीयों का जो मन आहत हो कर जी रहा था, अब वह अपनी गुलामी की मानसिकता से बाहर आ रहा है और अपने स्व को पहचानने लगा है। अपने मूल स्वभाव से कटकर कोई व्यक्ति, समाज या राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। भारत की पहचान प्रकृति की बनाई सभी चीजों को समान नजर से देखने की रही है। इसके सभी घटकों को बराबरी का सम्मान देने की रही है। सबके स्वास्थ्य और कल्याण की कामना और प्रयास करने की रही है। सबकी बातों को श्रद्धा भाव से सुनने की रही है। कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से करने की रही है। अहिंसा के रास्ते पर चल शांति स्थापित करने की रही है। यही हमारी ताकत रही है, जिसे हमने भुला दिया था। समय ने करवट बदली है। भारतीयों में अब आत्मविश्वास हर कदम पर नजर आता है। इसकी वजह से अब देशवासी अपने धर्म, संस्कृति, पर्व, त्योहार, भाषा आदि को किसी से कमतर नहीं मानते, बल्कि उस पर गर्व करते हैं। इस महाकुंभ के माध्यम से यह स्पष्ट हो चुका है कि हिंदू समाज ने अपना रास्ता पुनः खोज लिया है। महाकुंभ में आस्था का उमड़ा यह जनसैलाब इसका साफ-साफ संदेश दे रहा है कि अब भारत का समय आ गया है। अब इसकी प्रगति रोकी नहीं जा सकती। भारत जो सोने की चिड़िया था वह पुनः उसी रूप में पुनर्स्थापित हो रहा है।

महाकुंभ ने भारतवर्ष की वास्तविक पहचान- आध्यात्मिकता, धार्मिकता और सांस्कृतिक अस्मिता को दुनिया के सामने रखा है। इंटरनेट मीडिया ने महाकुंभ के माध्यम से भारत की इस पहचान का वैश्वीकरण करने में विशेष सहायता की है। भारत की पौराणिक चेतना में उपस्थित समुद्र मंथन एक घटना भर नहीं है। यह इस देश की चेतना में सतत चलने वाला चिरंतन अनुसंधान है। भारत की एकात्मता, इसकी संगठन शक्ति, इसके समावेशी, सहभाव और सामंजस्य का अप्रतिम उदाहरण है यह महाकुंभ। यह केवल एक मेला नहीं है, बल्कि भारत को उसके मूल से साक्षात्कार कराने का एक उत्सव है, जिसके द्वारा राष्ट्र अपनी दिव्यता को प्रदर्शित करता है। अपने लक्ष्य और दिशा का ध्यान करता है और फिर अपने लोगों के साथ एकजुट होकर उसे पाने के लिए निकल पड़ता है। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए भी तो इसी की दरकार होती है, जो इस बार के महाकुंभ ने हमें दिखाया है। इस महाकुंभ के आलोक में भारतीय मानस में व्यष्टि से समष्टि का भाव बीज रूप में स्थापित हुआ है। इसको अंतस में स्थापित करना है। अपनी गुरुता को विश्व के समक्ष रखना है, ताकि विकसित भारत के लक्ष्य को समय पूर्व पाया जा सके।

महाकुंभ में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। फाइल

यादगार विजय

यह भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित क्रिकेट मुकाबले की सुखद चर्चा का समय है। दुबई में भारत की शानदार जीत अपने आप में एक संदेश है, जिसकी गूंज पाकिस्तान को सकारात्मक रूप से प्रेरित करे, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जिन लफ्जों के साथ भारतीय टीम को हराने की अपील की थी, उसको जल्दी भुला नहीं जा सकता। क्रिकेट एक खेल है, पर इसे पाकिस्तान किसी धर्मयुद्ध की तरह खेलता है, यह बात पाकिस्तान के एकाधिक क्रिकेटर स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। बेशक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत विरोधी अपील से बचना चाहिए था। हालांकि, यह अच्छी बात है कि पाकिस्तान में समझदार लोगों की भी कमी नहीं है और वहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की पहले भी आलोचना हुई और अब भी हो रही है। एक बड़ा अंतर इस बार यह दिखा, पाकिस्तान में भारतीय टीम की खूब प्रशंसा और पाकिस्तानी टीम की आलोचना हो रही है। अनेक आला पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर, जो भारतीय टीम की आलोचना करते थकते नहीं थे, उन्होंने भी भारतीयों की मुक्त कंठ से सराहना की है।

भारतीय खिलाड़ियों ने अपने उम्दा खेल से जो अंतर पैदा कर दिया है, उसे पाकिस्तान में भी सहर्ष स्वीकार किया जा रहा है। पहले के दिनों में भी भारतीय खिलाड़ी अपने बड़प्पन को छोड़ते नहीं थे और अब नए खिलाड़ी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देते हैं। शुभमन गिल को आउट करने के बाद जिस अशालीन अंदाज में गेंदबाज अबरार अहमद इशारा कर रहे थे, कहीं न कहीं उनकी अच्छी गेंदबाजी पर उनका खराब व्यवहार हावी हो गया। ऐसे व्यवहार पर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम ने साफ कहा कि अबरार को मौका और जगह देखकर ही व्यवहार करना चाहिए। वाकई, यह एहसास जरूर होना चाहिए कि किसी भारतीय खेल प्रतिनिधि के साथ कोई गलत व्यवहार करता है, तो उसका संदेश 140 करोड़ भारतीयों तक पहुंचता है। मतलब, कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीयों के साथ अपने व्यवहार की समीक्षा करनी चाहिए। व्यापकता में देखें, तो पाकिस्तान के खराब व्यवहार की वजह से ही जो मुकाबला लाहौर या रावलपिंडी में हो सकता था, उसे दुबई में कराने की नौबत आई। लाहौर में मुकाबला होता और भारतीय टीम पाकिस्तान जाती, तो पाकिस्तान कितने फायदे में रहता, यह स्वयं वहां की सरकार के लिए विचारणीय है। शायद भारत में आईपीएल का हिस्सा बनकर अनेक पाकिस्तानी मालामाल हो रहे होते। भारत का तो सिर्फ इतना आग्रह है कि खेल और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते।

पाकिस्तान के खराब व्यवहार की वजह से ही जो मुकाबला लाहौर या रावलपिंडी में हो सकता था, उसे दुबई में कराने की नौबत आई। यह पड़ोसी देश कब सबक सीखेगा?

बहरहाल, दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ अगर छह विकेट से भारत की मिली जीत को याद किया जाएगा, तो उसमें विराट कोहली के विराट योगदान को जरूर देखा जाएगा। ध्यान रहे, पाकिस्तान व दुनिया के घातक तेज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर से एक पत्रकार ने पूछा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, तब शोएब ने टोकते हुए कहा था, विराट बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जब उन्हें बताया जाएगा कि मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है, तो वह जाग जाएंगे। शोएब बिल्कुल सही थे। वाकई, विराट पाकिस्तानी टीम को सामने देख जागे और अपने करियर का 51वां एकदिवसीय शतक जड़ दिया। किफायती गेंदबाजी, उम्दा क्षेत्ररक्षण, विस्फोटक बल्लेबाजी और सद्व्यवहार की यही लय भारतीय टीम के सेहरे में चार चांद लगाए रखे, क्रिकेटप्रेमी तो यही चाहेंगे।

अनुदान रोक अनुदार होता अमेरिका

हर्ष वी पंत | प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन

मानव विकास के लिए वह काम करता रहा है। इन सबको खत्म कर देना खुद अमेरिका की छवि के लिए ठीक नहीं। इससे धारणा बन सकती है कि अमेरिकी मदद मरोसेमंद नहीं रही।

ट्रंप प्रशासन ने रविवार को यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यानी 'यूएसएड' के 1,600 से भी अधिक कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया। अमेरिका के बाहर काम करने वाली इस एजेंसी के कई कर्मचारियों को वेतन देकर छुट्टी पर भेज दिया गया है और इसके आला अधिकारियों व कुछ खास कर्मचारियों को ही काम पर रखा गया है। यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार एलन मस्क के उस एजेंडे का हिस्सा है, जिसके तहत वे चुनाव से पहले इस एजेंसी के बजट और आकार को कम करने की बात किया करते थे। ये दोनों यूएसएड को 'अमेरिका प्रथम' नीति के तहत नए सिरे से गढ़ना चाहते हैं।

इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने 20 जनवरी को पद संभालते ही विदेशी सहायता भुगतान पर 90 दिनों की रोक लगा दी थी। भुखमरी और घातक बीमारियों से लड़ने वाले कार्यक्रमों से लेकर दुनिया भर में लाखों विस्थापितों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की राशि रोक दी गई है। सिर्फ सुरक्षा से जुड़े कुछ कार्यक्रमों, ड्रग्स के खिलाफ चल रहे अभियानों और मानवीय राहत की कुछ योजनाओं के लिए सीमित मदद जारी रखी गई है। अमेरिकी प्रशासन करीब 40 अरब डॉलर के आसपास के ऐसे सहायता कार्यक्रम चलाता है, जिसमें से महज 10 करोड़ डॉलर के अभियानों को ही राहत दी गई। साफ संकेत है कि ट्रंप प्रशासन यूएसएड के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने जा रहा है।

वास्तव में, राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार इस पर हमले किए हैं। पिछले दिनों उन्होंने इस एजेंसी को 'वामपंथी घोटालेबाज' बताया था और दावा किया कि इसकी फंडिंग रोककर इस घोटालेबाज को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस एजेंसी का नाम इसकी इमारत से हटा दिया गया है और अब वह स्थान अमेरिकी आव्रजन-प्रवर्तन एजेंसी 'कस्टम्स ऐंड बॉर्डर पेट्रोल' के कर्मियों को देने की बात कही गई है। यह सब इसलिए किया गया है, क्योंकि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी विदेशी जमीन पर अमेरिकी खर्च को लेकर आग्रही है और इसे हर हाल में रोकना चाहती है। ट्रंप प्रशासन मानता है कि इस तरह की फंडिंग को लेकर अमेरिका में नाराजगी है और ये अमेरिकी हितों को पूरा भी नहीं कर रहीं। एलन मस्क तो इस एजेंसी को 'आपराधिक संस्था' तक कह चुके हैं।

इन सबसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राहत व मानवीय मदद के कार्यों में जो मदद मिल रही थी, उसमें बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि अमेरिका इस मदद में सबसे ज्यादा पूंजी मुहैया कराने वाला देश रहा है। मानव विकास के लिए यह काफी काम करता रहा है। इन सबको एक झटके में खत्म कर देना खुद अमेरिका की छवि के लिए ठीक नहीं है। इससे यह धारणा बन सकती है कि अमेरिकी मदद भरोसेमंद नहीं रही। चूंकि कई देशों में अमेरिकी मदद से राहत एवं पुनर्वास के काम चल रहे हैं, जाहिर है, उन सबके भविष्य पर अब एक सवालिया निशान लग गया है।

बेशक, ट्रंप और मस्क चाहते हैं कि 'सबसे पहले अमेरिका' की नीति के अनुसार अमेरिकी धन खर्च हो, लेकिन इसे एकतरफा बंद करना आसान नहीं होगा। उन्हें यह बताना होगा कि आखिर कैसे इस एजेंसी के तहत मिलने वाली मदद अमेरिकी हितों के खिलाफ रही है। यूएस कांग्रेस (संसद) में इस बाबत प्रस्ताव लाना होगा, जहां डेमोक्रेट के विरोध मुखर हो सकते हैं। इस एजेंसी का गठन 1961 में किया गया था और इसका प्राथमिक उद्देश्य मानवीय सहायता पहुंचाना ही है। 60 से अधिक देशों में इसके कार्यक्रम चल रहे हैं। यह एजेंसी खुद संबंधित देशों में काम नहीं करती, बल्कि स्थानीय एजेंसी को फंड देकर काम करवाती है।

सवाल है कि भारत जैसे देश इससे कितने प्रभावित होंगे? भारत चूंकि अगले चंद वर्षों में शीर्ष तीन आर्थिक ताकतों में शुमार होने वाला है, इसलिए इसकी सेहत पर शायद ही कोई असर पड़े, मगर कई ऐसे देश हैं, जहां इस एजेंसी का काम काफी विस्तार ले चुका है। स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, परिवहन, सुखा, टीकाकरण, महामारी जैसे तमाम क्षेत्रों में सुरक्षात्मक उपायों की दिशा में इन अमेरिकी पैसों का इस्तेमाल होता है। चूंकि ज्यादातर पैसा गरीब और अविकसित देशों को जाता है, इसलिए वहां ट्रंप का नया आदेश काफी रुकावटें पैदा कर सकता है। इससे आने वाले दिनों में अमेरिका की जगह अगर दूसरे देश लेते हुए दिखें, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि चीन खुलकर अमेरिका को टक्कर दे रहा है। ऐसे में, वह अमेरिकी प्रशासन के नए फैसले का इस्तेमाल अपनी विस्तारवादी नीतियों में कर सकता है, जिससे पूरे विश्व का नुकसान होगा।

राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि जो काम यूएसएड के माध्यम से हो रहा है, उसमें अमेरिकी करदाताओं के पैसा बेजा इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी जारी किए हैं। मगर ऐसा करते हुए ट्रंप ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका अब पुराने ढर्रे पर चलने को तैयार नहीं है। इस पैसे का इस्तेमाल वह अपनी सुरक्षा मजबूत करने में करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री को इस बाबत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।

ट्रंप बेशक यह दावा करते हैं कि अमेरिकी मदद को कम करने की सोच आम अमेरिकियों की है, लेकिन इस मदद ने अमेरिका की छवि एक 'सॉफ्ट पावर' की गढ़ी। जाहिर है, अब अमेरिकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। ट्रंप यह भी मानते हैं कि इस तरह की मदद का इस्तेमाल अन्य कामों में हुआ है और भारत का नाम भी उन्होंने लिया है। मगर भारतीय विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिकी मदद वाली परियोजनाएं चुनाव से जुड़ी हुई नहीं रही हैं। उन पैसों का इस्तेमाल कृषि और खाद्य सुरक्षा, पानी, स्वच्छता, अक्षय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में हुआ है। यानी, ट्रंप के दावों से भले ही भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के प्रयास किए जा रहे हों, लेकिन असलियत में इस बाबत सुबूत नहीं मिलते।

साफ है, यूएसएड का भविष्य अब उलझ गया है। रिपब्लिकन जहां इसे बंद करने पर आमादा हैं, तो वहीं डेमोक्रेट राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम को असांविधानिक बता रहे हैं। बेशक, इस मसले का आखिरी समाधान कांग्रेस में होगा, लेकिन इस सबसे अमेरिका की विदेश नीति और विकास नीति जिस तरह प्रभावित हो रही है, उससे पूरी विश्व व्यवस्था पर असर पड़ना तय है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हर शहर और गली में बढ़ रही वाहन पार्किंग की पीड़ा

नितिन पाई | निदेशक, तक्षशिला संस्थान

भारत में बहुत कम लोगों ने लॉस एंजिल्स स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डोनाल्ड शुप के बारे में सुना होगा, जो इस महीने की शुरुआत में दुनिया छोड़ गए। यह दुखद है, क्योंकि उनके जीवन के योगदानों में भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का जवाब छिपा है- हमारे शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। शुप पार्किंग नीति जैसे विषय में दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे। उनके एक छात्र ने उनकी प्रशंसा में कहा था, डोनाल्ड पार्किंग के पुरोधा हैं। वह जो किताब पीछे छोड़ गए, उसका शीर्षक है *द हाई कॉस्ट ऑफ फ्री पार्किंग*, जिसे देश के हर अर्थशास्त्री, शहरी योजनाकार, सिविल सेवक और शहरी प्रशासक को पढ़ना चाहिए।

भारत के शहरों में जगह-जगह जाम लगने का एक मुख्य कारण खड़े या पार्क किए गए (और डबल पार्क किए गए) वाहन हैं, जो ट्रैफिक को धीमा और तनावपूर्ण बना देते हैं। आर्थिक, स्वास्थ्य और पर्यावरण लागतों के अलावा, यातायात की भीड़ हमारी सामाजिक पूंजी को भी नष्ट कर देती है। मैंने खराब यातायात को राष्ट्र-विरोधी करार दिया था, क्योंकि यह हमारे पहले से ही कमजोर भाईचारे को नुकसान पहुंचाता है। यह हमारे व्यवहार के सबसे बुरे रूपों को रोजाना हमारे सामने ला खड़ा करता है। हमारी सड़कों को जाम से मुक्त करना शहरी नीति की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रो डोनाल्ड शुप हमें न केवल यह बताते हैं कि क्या करना है, बल्कि यह भी बताते हैं कि इसे कैसे करना है।

अगर पार्किंग शुल्क से मिली राशि का इस्तेमाल स्थानीय क्षेत्रों में सुधार के लिए किया जाए, तो उच्च शुल्क को भी लोगों का समर्थन मिलेगा।

एक, सड़क पर पार्किंग के लिए सही मूल्य तय करें। दो, स्थानीय सार्वजनिक सेवाओं के लिए ही पार्किंग शुल्क राजस्व का उपयोग करें। इन दो बिंदुओं पर भारत में जरूर काम होना चाहिए। भारतीय सड़कों पर बहुत अधिक कारें खड़ी होने की वजह यह है कि ज्यादातर जगह पार्किंग मुफ्त है। मुफ्त पार्किंग के चलते हमें संभीर आर्थिक और पर्यावरणीय कीमतें चुकानी पड़ती हैं। यह अपने अमीर नागरिकों के लिए सामाजिक संसाधन का अनुचित हस्तांतरण भी है। हमारे स्थानीय निकाय घाटे में चलते हैं, जबकि पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर वाहनों को सार्वजनिक संपत्ति का लाभ दिया जाता है। सड़क पर या कहीं किनारे जिसे जहां मर्जी सरकारी जमीन पर मुफ्त वाहन खड़े कर देता है।

ध्यान रहे, भारत का हर शहर अपने व्यस्ततम इलाकों में पार्किंग शुल्क वसूलकर आसानी से पांच प्रतिशत से अधिक राजस्व जुटा सकता है। फिर भी, भारत में बहुत कम शहरों ने सशुल्क पार्किंग नीति को लागू किया है। शुप की सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि यह है कि ऐसी नीतियों को सेवक बनाया जा सकता है। यदि पार्किंग-राजस्व को बेहतर सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से पारदर्शी तरीके से वापस स्थानीय स्तर पर ही खर्च किया जाए। पार्किंग से मिला पैसा राज्य की राजधानी या नई दिल्ली में सरकारी खजाने में चला जाए, तो नागरिक सशुल्क पार्किंग योजनाओं का विरोध करेंगे, पर यदि वे देखेंगे कि पैसा बेहतर फुटपाथ, कचरा निकासी, बस स्टॉप और स्ट्रीट लाइट के रूप में वापस आ जाता है, तो वे शुल्क चुकाने के लिए उत्साहित होंगे। राजकोषीय व्यवस्था जितनी व्यापक होगी, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यह वह तरकीब है, जो हमारे शहर भूल रहे हैं। इससे कई फायदे हैं, सार्वजनिक खर्च बढ़ेगा। सरकारी विनियमन घटेगा। ऊर्जा की खपत, वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम होगा।

तो फिर सशुल्क पार्किंग को इतना विरोध क्यों झेलना पड़ता है? शुप बताते हैं, क्योंकि सभी लोग मुफ्त में अपने वाहन खड़े करना चाहते हैं। वाहन रखने वाले हर व्यक्ति की मुफ्त पार्किंग में व्यक्तिगत रुचि होती है।

जब सिंगापुर ने कार के स्वामित्व पर उच्च कर और बाद में इलेक्ट्रॉनिक रोड प्राइसिंग की शुरुआत की, तो सरकार ने जोर देकर कहा कि इन राजस्वों का उपयोग सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और सब्सिडी देने के लिए किया जाएगा। इससे सिंगापुर में सबको फायदा हुआ। हालांकि, भारत में केवल पार्किंग सुधारने से राहत नहीं मिलेगी। हम भारत के बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने के लिए सड़कें चौड़ी कर सकते हैं, ज्यादा फ्लाईओवर बना सकते हैं, पर भारतीय जैसे-जैसे अमीर होते जाएंगे, वैसे-वैसे वाहनों का ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। हमें जरूरी सुविधाओं का विस्तार जारी रखना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

प्रयास से खुशी नहीं मिलती

हमारा समस्त जीवन प्रायः प्रयास पर, किसी न किसी संकल्प पर आधारित रहता है। संकल्प या प्रयास के बना किसी कर्म की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा सामाजिक, आर्थिक व तथाकथित आध्यात्मिक जीवन प्रयासों की एक कड़ी ही है, जिसका अंत किसी उपलब्धि, किसी परिणाम में होता है और हम सोचते हैं कि प्रयास अनिवार्य है, आवश्यक है।

हम प्रयास क्यों करते हैं? सरल भाषा में कहा जाए, तो क्या इसीलिए कोशिश नहीं करते कि किसी फल की प्राप्ति हो, हम कुछ बन सकें, किसी लक्ष्य को हासिल कर सकें? हमें लगता है कि प्रयास के बिना हम कहीं थम जाएंगे। हमारे पास उस लक्ष्य की एक कल्पना होती है, जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते हैं और यह संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। यदि हम अपने को बदलना चाहते हैं; यदि हम अपने में मौलिक परिवर्तन चाहते हैं, तो पुरानी आदतों को खत्म करने के लिए जबरदस्त कोशिश करते हैं। इस प्रकार, कुछ पाने, यहां तक कि किसी प्रकार जीवित रहने के लिए भी हम अनवरत प्रयास के आदी हो जाते हैं।

क्या ये सभी प्रयास स्व की ही गतिविधि नहीं हैं? क्या ये अहं-केंद्रित गतिविधि नहीं हैं? जब हम स्व के केंद्र से प्रयास करते हैं, तो अनिवार्यतः उसका परिणाम और अधिक द्वंद्व, और अधिक भ्रांति, और अधिक दुख ही होगा, फिर भी हम प्रयत्न पर प्रयत्न किए चले जाते हैं? प्रयास की आत्म-केंद्रित क्रिया हमारी किसी समस्या को हल नहीं करती, बल्कि हमारी भ्रांति, हमारे दुख और कष्ट में वृद्धि ही करती है। हम यह जानते हैं और फिर भी निरंतर यह आशा बनाए रखते हैं कि हम प्रयास की इस स्व-केंद्रित क्रिया द्वारा किसी न किसी प्रकार आगे निकलने का कोई मार्ग खोज ही लेंगे।

मैं समझता हूं कि यदि प्रयास के आशय को समझ लें, तो जीवन की सार्थकता को भी समझ जाएंगे। क्या कभी प्रयास से खुशी आती है? क्या आपने कभी खुश होने का प्रयास किया है? क्या आपको नहीं लगता कि यह असंभव है? आप खुश होने की कोशिश करते हैं, फिर भी खुश नहीं हैं। दमन, नियंत्रण या भोग में आनंद नहीं पाया जा सकता।

क्या कभी प्रयास से खुशी आती है? आपको नहीं लगता कि यह असंभव है? आप खुश होने की कोशिश करते हैं, फिर भी खुश नहीं हैं। दमन, नियंत्रण या भोग में आनंद नहीं पाया जा सकता।

नहीं पाया जा सकता है। आप भोग में लिप्त हो सकते हैं, लेकिन अंत में कटुता ही हाथ लगती है। आप भले ही दमन या नियंत्रण करते रहें, पर एक छिपा हुआ संघर्ष सदा बना रहता है। अतः सुख-शांति प्रयास से नहीं मिलती, और न ही आनंद नियंत्रण या दमन से मिलता है। फिर भी हमारा समस्त जीवन दमन, नियंत्रण और पश्चत्ताप से भरे हुए भोगों की शृंखला है। क्या हम इसी आशा में निरंतर प्रयास नहीं करते रहते कि हम कुछ ऐसा पा लेंगे, जो हमें शांति और प्रेम का एहसास देगा? लेकिन प्रेम अथवा समझ का संघर्ष से भला क्या संबंध!

जे कृष्णमूर्ति

गैरी कास्परोव | पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन

यूक्रेन और इसके बाशिंदों की जेलेंस्की कितनी परवाह करते हैं, यह ट्रंप और मस्क जैसे लोगों की समझ के बाहर है, वे दोनों केवल अपनी ताकत और निजी छवि की परवाह करते हैं।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 25 फरवरी, 1950

गम्भीर परिस्थिति

पूर्वी पाकिस्तान से पिछले दिनों चिन्ताजनक समाचार आते रहे हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में पहले जो हो चुका है, शुक्र उसकी पुनरावृत्ति-सी पूर्वी पाकिस्तान में भी की जा रही है, या करने की पेशबन्दी है, ऐसा कुछ उन समाचारों से भासित होता है। उसकी प्रतिक्रिया हमारे देश की कलकत्ता महानगरी में भी कुछ हुई और ऐसा भय अस्वाभाविक नहीं था कि पश्चिमी पाकिस्तानी घटनाओं के प्रतिक्रिया-स्वरूप हमारे देश के (पूर्वी) पंजाब में व स्वयं राजधानी दिल्ली में भी जो हुआ, उसकी हमारे देश में पुनरावृत्ति न हो। किन्तु हमारे देश पर जिनका शासन है, उनकी नीति स्पष्ट है और उन्होंने अल्पसंख्यकों को निर्भयता का जो वचन दिया है, उस पर वे ईमानदारी से दृढ़ हैं। यही कारण है कि हमारी तरफ सख्ती और निष्पक्षता से काम लेकर स्थिति को जल्दी सम्हाल लिया गया, जबकि दूसरी ओर न तो स्थिति सम्हली मालूम पड़ती है और न उसे सम्हालने की ही सच्ची वृत्ति मालूम पड़ती है। हमारे प्रधानमंत्री प. जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में गुरुवार (२३ फरवरी) को इस संबंध में जो वक्तव्य दिया, वह कुछ इसी बात का द्योतक है।

नेहरू जी ने अपने लिखित भाषण में भावना के बजाय तथ्यों पर अधिक ध्यान रखा है और गर्मी के बजाय नर्मी ही उसमें अधिक है। ''पिछले दिनों पूर्वी बंगाल पर एक प्रकार से लीह-आवरण पड़ा रहा, जिसके कारण सही सूचनाएं प्राप्त नहीं हो सकीं।'' यह बताते हुए उन्होंने उन रहस्यों का उद्घाटन किया है जो जांच-पड़ताल के बाद ठीक मालूम पड़े। यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ''हमारे सामने जो समस्या है वह इतनी गम्भीर है कि उसे राजनैतिक प्रचार का साधन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के करोड़ों व्यक्तियों का भविष्य उससे प्रभावित होता है।'' फिर भी संयम से काम लेते हुए भी, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ''पूर्वी बंगाल में जो कुछ हुआ है, वह उससे कहीं अधिक गम्भीर है जो कलकत्ता में या पश्चिमी बंगाल के एक-दो स्थानों में हुआ है। और दोनों में कोई समानता नहीं है।'' यही नहीं, आगे वह यह भी कहते हैं कि ''पाकिस्तान के यदि सभी अल्पसंख्यक नहीं तो उनमें से अधिकांश सुरक्षा की आशा खो बैठे हैं और वे भय तथा आशंका से ग्रस्त हैं, यह हमें स्पष्ट दिखाई देता है।''

संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर सवाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों से संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिह्न लग गया है। ट्रंप ने पद संभालते ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपने देश का बाहर कर लिया। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन व पेरिस जलवायु समझौते से भी निकलने का एलान किया तथा अन्य एजेंसियों को दी जाने वाली धनराशि में कटौती कर दी है। ये एजेंसियां पूरी दुनिया में शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में काम करती हैं, लेकिन अमेरिका ने एकतरफा फैसला लेते हुए इनसे खुद को अलग कर लिया है, जो पूरी दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सवाल यही है कि संयुक्त राष्ट्र अपने किसी सदस्य देश को जब बाध्य ही नहीं कर सकता, तो फिर उसकी आहमियत क्या है? इससे स्वाभाविक तौर पर उसकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका अधिनायकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिसके खिलाफ ही संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया है। तब यह माना गया था कि यह वैश्विक संस्था पूरी दुनिया में सद्भाव और शांति कायम करने व तरक्की के लिए समान भाव से काम करेगी। मगर अब ऐसा होते नहीं दिख रहा। अमेरिका अपनी तरफ से फैसले लेते हुए पूरी दुनिया पर उसे थोप रहा है। अब टैरिफ बढ़ाने का ही मामला देखिए। उसने कुछ देशों के लिए टैरिफ बढ़ा दिए हैं, जबकि कई अन्य को ऐसा करने की धमकी दी है। उसे लगता है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, पर वास्तव में ऐसे कदमों से खुद उसकी आर्थिकी भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। इस प्रकार के फैसले अमेरिका की कथनी और करनी में अंतर बता रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र चुपचाप इसे देख रहा है। अगर हम इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र जैसी सत्ता को मजबूत करना होगा। यह मजबूत होगी, तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर सहयोग भी बढ़ेगा। अभी इसकी सख्त जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र किसी देश के एकतरफा फैसले के विरुद्ध उचित कार्रवाई तभी कर सकेगा, जब सभी देश उसे सहयोग देंगे। मगर फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं।

केएन शर्मा, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
संयुक्त राष्ट्र

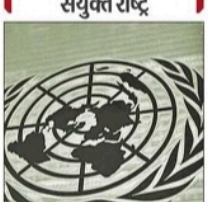

अस्तित्व पर सवाल

संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता अब कागजी खानापूर्ति से अधिक कुछ भी नहीं है। आपस में बंटी हुई दुनिया अपने-अपने अहं की पुष्टि के लिए मानव सभ्यता को गंभीर संकट के मुहाने पर धकेलती जा रही है।

श्रद्धा नंद फोंदणी, टिप्पणीकार

हमेशा महत्वपूर्ण बनी रही यह संस्था

संयुक्त राष्ट्र कोई ऐसी संस्था नहीं है कि किसी एक देश की हरकत से उसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ जाए। निस्संदेह, अमेरिका एक बड़ा देश है और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों की वह सबसे अधिक आर्थिक मदद करता है, लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं कि उसे इस संस्था को अपनी उंगली पर नचाने की छूट दे दी जाए। अगर वह इससे बाहर निकलना चाहता है, तो निकल सकता है। उसकी जगह लेने के लिए कई देश खड़े हैं। वे दिन अब बीत गए, जब अमेरिका विश्व व्यवस्था को नियंत्रित करता था। अब कई उभरते देश (जो वाशिंगटन को बराबरी का टक्कर दे सकते हैं।

क्या कोई इस बात को नकार सकेगा कि संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं ने दुनिया भर में युद्ध, गरीबी, भुखमरी या फिर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? यहां तक कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय भी इसकी एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जिससे बाहर निकलने का एलान अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है, दुनिया भर के देशों को कोरोना टीके उपलब्ध कराए। रेडक्रॉस जैसी इसकी एजेंसी युद्ध अथवा संघर्ष में उलझे इलाकों में जाकर आम लोगों तक मानवीय व स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराती है। इसके कार्यकर्ता पीढ़ितों की मदद में अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं, लेकिन कभी रुकते नहीं। कल्पना कीजिए, यदि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था हमारे पास न होती, तो फिर दुनिया की क्या तस्वीर होती?

यहां यूनीसेफ की चर्चा भी जरूरी है। बच्चों को भूख, गरीबी और विस्थापन की त्रासदियों से उबारने में यूनीसेफ का अहम योगदान है। इसी तरह यूनेस्को जैसी एजेंसी दुनिया भर में प्राचीन धरोहरों और स्मारकों की रक्षा व संरक्षण का काम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना ने कई युद्धरत क्षेत्रों और देशों में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। जगह-जगह दक्षिणपंथी फासीवादी सरकारें सत्ता में आ गई हैं, जिसकी एक मिसाल खुद अमेरिका है। ये सरकारें अल्पसंख्यकों का दमन करती हैं। संयुक्त राष्ट्र ऐसी दमनात्मक कार्रवाइयों के खिलाफ लोगों को ताकत देता है। यही कारण है कि अपनी तमाम सीमाओं और कमियों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। अमेरिका भले ही इसे चोट पहुंचाने के लिए कई तरह के उपाय करे, लेकिन इसने जो मकाम बना लिया है, उससे इसे डिगा पाना मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र एक विश्व व्यवस्था के तौर पर हमारे बीच हमेशा बना रहेगा।

दीपक, टिप्पणीकार

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 25 फरवरी • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

केवल प्रकाश का अभाव ही अंधकार नहीं, प्रकाश की अति भी मनुष्य की आंखों के लिए अंधकार है
-स्वामी रामतीर्थ

मेलोनी का मास्टर स्ट्रोक

इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी ने वाशिंगटन में आयोजित कंजर्वेटिव पॉलटिक्स एक्शन कांफ्रेंस में वामपंथ की खुलकर आलोचना करते हुए रूढ़िवादी बातों पर जोर दिया। वीडियो लिंक द्वारा दिये भाषण में मेलोनी ने कहा 90 के दशक में बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर के वैश्विक वामपंथी उदारवादी नेटवर्क बनाने पर उन्हें अनुभवी व प्रतिष्ठित राजनेता कहा गया। आज जब ट्रंप, मेलोनी, (अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर) माइली या शायद (नरेन्द्र) मोदी बात करते हैं तो उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा कहा जाता है। मेलोनी ने कहा यह दोहरा मापदंड है, लेकिन हम इसके आदी हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि वे हम पर चाहे जितना कीचड़ उछालें, लोग उनके झूठ पर अब भरोसा नहीं करते। आगे उन्होंने कहा, ट्रंप की जीत से वामपंथी घबराये हुए हैं। उदारवादी नेटवर्क के तौर पर वर्णित संगठन की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने वामपंथियों पर पाखंड करने और विश्व स्तर पर रूढ़िवादी नेताओं के उदय पर उन्मादी प्रक्रियाओं पर सीधे वार किए। अति दक्षिणपंथी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की नेता मेलोनी के ये तेवर रोम में उनके राजनैतिक विरोधियों के लिए यह सांप लोटने सरीखा है। मेलोनी के विचारों से ट्रंप की यूरोप के प्रति अमेरिकी नीति में बदलाव तथा यूरोपीय सहयोगियों के दरम्यान तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के संकेत स्पष्ट नजर आते हैं। यूरोप के व्यापार असंतुलन व टैरिफ बढ़ाने के ऐलान के बाद से नया विवाद जारी है। कहा जा सकता है कि नये अमरीकी प्रशासन को वह किसी भी कीमत पर नाराज करने को राजी नहीं हैं। इस कांफ्रेंस का मकसद ही दुनिया में रूढ़िवादियों की सबसे बड़ी व प्रभावशाली सभा के रूप में दुनिया के समक्ष अपनी ताकत का इजहार करना है। तय रूप से वर्तमान समय में मेलोनी या अन्य रूढ़िवादी नेताओं ने वामपंथियों पर तीखे वार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वे जनता के समक्ष उदारवादियों की कलई उतारने और संगठित रूप से अपनी जड़े मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। व्यापक प्रचार व तीखे तेवरों के भरोसे वे अपने मकसद में काफी हद तक सफल भी होते जा रहे हैं। विचारणीय है कि बीते दशक में यूरोप में रूढ़िवादी व दक्षिणपंथियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इस पर चिंता भले ही जताई जा रही है, परंतु मतदाताओं की बदलती विचारधारा पर गहन विश्लेषण की जरूरत को भी बरगलाया जाना अनुचित नहीं कहा जा सकता। मेलोनी के तेवरों से रूढ़िवादियों को सीना चौड़ा करने का फिर से सुनहरा मौका हाथ लगा है।

भारत का 'विराट' दबदबा

भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी क्रिकेट मुकाबला होता है तो क्रिकेट का बुखार चरम पर पहुंच जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबला भी इससे कोई अलग नहीं था। पर भारत ने विराट के शतक से मुकाबले को जिस तरह एकतरफा बनाकर जीता, उससे लगा कि इन मुकाबलों में उन्माद की कमी तो पहले से ही महसूस की जा रही थी पर अब रोमांच में कमी भी दिखने लगी है। इसकी एक वजह तो भारत के मुकाबले पाकिस्तान टीम का काफी कमजोर हो जाना है। दूसरा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों में किसी भी हाल में हार नहीं मानने वाला जज्बा भी नहीं दिखा। यही वजह है कि भारत के छह विकेट से जीत पाकर सेमीफाइनल में स्थान पक्का करने पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी भारतीय टीम की तारीफ करते नजर आ रहे थे। पाकिस्तान के लिए ग्रुप में लगातार दूसरा मैच हारना इसलिए भी खराब है कि वह करीब तीन दशक बाद आईसीसी टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है और बहुत संभावना है कि वही सेमीफाइनल में खेलती नजर नहीं आए। वैसे अगर वह किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच गई तो शायद वहां के क्रिकेटप्रेमी इस हार को पचा पाएंगे। भारत ने 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के हाथों हुई हार का हिसाब ही बराबर नहीं किया है बल्कि यह भी दिखा दिया है कि दोनों टीमों में अब काफी फर्क आ चुका है। भारत के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में पहले मैच में लंबे समय बाद वापसी करने वाले मोहम्मद शमी ने पांच विकेट लेकर अपनी क्षमता को फिर से प्रदर्शित किया। वहीं इस मैच में विराट कोहली ने शतक लगाकर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। वह पिछले कुछ समय से बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे थे। पर विराट ने जिस तरह इस महत्त्वपूर्ण मैच में अपनी रंगत की वापसी की, उस पर हरभजन का यह कहना सही था कि विराट के लिए रंगत पाना का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता था। भारतीय टीम 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद एक दशक से ज्यादा समय तक कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकी थी, लेकिन पिछले साल टी-20 विश्व कप जीतकर सूखे को खत्म किया था। अब वह यदि लगातार दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीत लेता है तो भारत का डंका बजेगा। साथ ही रोहित शर्मा की कप्तानी और गौतम गंभीर का कोचिंग पर सवाल उठाने वालों के मुंह भी बंद हो जाएंगे।

विमर्श/सोनम लववंशी

पहचान पर पहरा

समाज में भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। यह सोच, संस्कार और व्यवस्था का दर्पण होती है। जब भाषा में भेदभाव और रूढ़िवादिता समाहित हो जाती है, तो वह समाज की मानसिकता को दर्शाती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बात हो तो उनके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण पर ही चर्चा होती है, लेकिन भाषाई हिंसा पर किसी का ध्यान नहीं जाता है।

अभी हाल ही में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का हालिया फैसला, जिसमें तलाकशुदा महिलाओं को 'डाइवोर्सी' कहने पर रोक लगाई गई है, इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। विडंबना देखिए 21वीं सदी में हमें यह बताने की जरूरत पड़ रही है कि महिलाओं को उनके नाम से पहचाना जाए, न कि उनकी वैवाहिक स्थिति से? लेकिन सच तो यही है कि इस मामले में अदालत को दखल देना पड़ा, क्योंकि समाज की भाषा अब भी 'पति-परमेश्वर' युग में ही अटकी हुई है। दरअसल, यह शब्दों का खेल नहीं, मानसिकता की लुका-छिपी है। पुरुष अगर शादीशुदा है तो जिम्मेदार, अविवाहित है तो सफल और फोकस्ड, विधुर है तो दुखियारा और तलाकशुदा है तो आजाद पंछी, लेकिन जब बात महिला की हो तो अविवाहित होने पर उसे बेचारी कहकर संबोधित किया जाता है। शादीशुदा है तो सुहागिन देवी और विधवा है तो अबला, तलाकशुदा है तो डाइवोर्सी। अब भला कोई बताए, महिला की असली पहचान उसकी वैवाहिक स्थिति है या उसकी उपलब्धियां? अदालत ने सही कहा कि तलाकशुदा महिला को केवल उसकी वैवाहिक स्थिति से पहचान देना पूरी तरह अनुचित है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस फैसले के बाद सरकारी दफ्तरों में फॉर्म भरते समय महिलाओं से 'मिस/मिसेज/डाइवोर्सी' पूछना बंद होगा? महिलाओं की पहचान उनकी काबिलियत और नाम से होनी चाहिए, न कि उनके वैवाहिक दर्जे से, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब यह सोच हर सरकारी दफ्तर, हर फॉर्म, हर अखबार और हर बातचीत में झलकेगी। जब समाज महिलाओं को सिर्फ उनके नाम और काम से जानेगा, न कि उनकी 'शादी की स्थिति' से। जब 'डाइवोर्सी' एक पहचान नहीं, बल्कि बीते कल की एक घटना भर रह जाएगी।

विदेशी भूमिका का सच

भारत में चुनाव

अवधेश कुमार

भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएस एड) के माध्यम से 21 मिलियन डॉलर यानी 182 करोड़ रुपये आने की सूचना ने पूरे देश में खलबली पैदा की है। ट्रंप प्रशासन के अंदर नवनिर्मित डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डोजे) यानी सरकारी दक्षता विभाग ने उसकी जानकारी देते हुए सूची जारी की।

शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रोकने की घोषणा की और कहा कि भारत के पास स्वयं काफी रुपया है तो हम क्यों दें। उस समय ऐसा लगा मानो भारत द्वारा अमेरिकी सामग्रियों पर लगने वाले आयात शुल्क के विरुद्ध कदम उठा रहे है। फिर उन्होंने मियामी और उसके बाद वाशिंगटन डीसी के आयोजनों में कहा कि हमें भारत में मतदान बढ़ाने पर 21 मिलियन खर्च करने की आवश्यकता क्यों है? मुझे लगता है कि वे किसी और को जिताने की कोशिश कर रहे थे। हमें भारत सरकार को बताना होगा। क्योंकि जब हम सुनते हैं कि रूस ने हमारे देश में 2 करोड़ डॉलर का खर्च किया है तो यह हमारे लिए बड़ा मुद्दा बन जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा कह रहे हैं तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। हमारे पास भारतीय चुनाव में हस्तक्षेप को साबित करने के लिए सटीक प्रमाण नहीं हैं। कुछ तथ्यों के आधार पर इसकी विवेचना की जा सकती है। डोजे द्वारा यूएस एड की जारी सूची में 15 तरह के कार्यक्रम के लिए धन देने की बात है। इनमें एक दुनियाभर में 'चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढ़ीकरण' के लिए 48.6 करोड़ डॉलर यानी 4200 करोड़ का अनुदान था। इसी में भारत की हिस्सेदारी 182 करोड़ रुपये की है।

बांग्लादेश को मिलने वाली 251 करोड़ रुपये बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा था। विश्व में चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता अमेरिकी प्रशासन को क्यों महसूस हुई? बांग्लादेश में राजनीतिक सुधारों के लिए अमेरिकी सहायता राशि की जरूरत क्यों थी? मोजाम्बिक में पुरुष खतना कराएं, कंबोडिया में स्वतंत्र आवाज मजबूत हो तो प्राग में नागरिक समाज अंदर सशक्त हो इनका केवल समाजसेवा या उस देश का हित उद्देश्य नहीं हो सकता। इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य हैं। सच है कि 2012 में भारत के चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के साथ एमओयू यानी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एसवाई कुरैशी ने इन आरोपों और समाचारों को निराधार बताया है कि आईएफएससी से धन आयोग को स्थानांतरित हुआ था। कहीं नहीं कहा गया है कि इसने सीधे चुनाव आयोग को पैसा दिया। इस एजेंसी को यूएस एड से धन मिलता था और यह जार्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ संबद्ध है। ऐसी संस्थाएं किसी माध्यम से अपनी भूमिका को वैधानिकता का आवरण देने की दृष्टि से समझौते करती हैं और फिर अपने अनुसार कार्य करती है। ध्यान रखिए 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव था और उसके पहले उप्र, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर का। 2013 में पहले कर्नाटक उसके बाद मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का। भारतीय चुनाव और राजनीति में विदेशी भूमिका की बात पहली बार नहीं आई है। मोदी सरकार गठित होने के बाद से इसका चरित्र और व्यवहार बदला है किंतु हमारे देश में यह बीमारी लंबे समय से है। जब देश के नेता नौकरशाही, बुद्धिजीवी, पत्रकार, एक्टिविस्ट आदि छोटे-छोटे लाभ के लिए खिलौना बनने को तैयार हो जाएं तो कुछ भी हो सकता है। शीतयुद्ध काल में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धाएं थीं। दोनों अपने प्रभाव के लिए हस्तक्षेप करते थे। भारत में 1967, 77, 80 के चुनाव में विदेशी भूमिका की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। सोवियत संघ के विघटन के बाद 'मित्रोखिन पेपर' नाम से ऐसी जानकारियां आईं जिनसे पढ़ने वाले भौंचक रह गए थे। वासिली मित्रोखिन, जो सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी से संबद्ध थे, और क्रिस्टोफर एन्ड्रयूज ने अपनी पुस्तक में खुलासा किया कि केजीबी ने भारत के अनेक समाचार पत्रों एक्टिविस्टों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, नेताओं पर उस समय अरबों रुपये खर्च किए। भारत में अमेरिका के राजदूत रह चुके डेनियल मोयनिहान ने पुस्तक 'ए डैजरस प्लेस' में लिखा है कि भारत में कम्युनिस्टों के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका ने भारतीय नेताओं को धन दिए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे संदेह बढ़ा। 2019 में दोबारा उनके सत्ता में लौटने के बाद अलग तरह के स्वरूपों में आंदोलन हुए। इनमें नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध शाहीनबाग धरना और उसके समर्थन में देश और दुनिया में सोशल मीडिया से लेकर अन्य अभियान तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का सरकार के विरुद्ध सीधे बयान देना शामिल है।

कृषि कानून के विरुद्ध हुए आंदोलन में भी हमने देखा कि देश के बाहर से टूलकिट बनाकर अभियान चलाए जा रहे थे। इस तरह के आंदोलन भारत ने कभी देखे नहीं जिसमें प्रत्यक्ष हिंसा नहीं हो, पर उग्रता और हठधर्मिता ऐसी कि मुख्य सड़क पर धरना दो, आवश्यकतानुसार निर्माण भी कर लो और बैठे रहो, किसी सूरत में हटो नहीं। विदेशी हस्तक्षेप की बातें भारत के अलावा दूसरे देशों और नेताओं द्वारा भी कही जा रहा है। विश्व के अनेक देशों की चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में विदेशी शक्तियों और संस्थाओं की भूमिका सामने आती रही हैं। माइक्रोसाफ्ट ने डीपफेक और एआई के माध्यम से भारतीय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशों पर चेतावनी दिया था।

भारत पर विस्तृत अध्ययन नहीं आया, किंतु 2019 के चुनाव में ज्यादातर देशों ने स्वीकार किया कि झूठ और अफवाह फैला कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें की गईं। 2024 के चुनाव में हमने देखा कि संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा जैसे झूठ ने भूमिका अदा की। इसमें सोशल मीडिया, मुख्य मीडिया, एआई की पूरी भूमिका थी। दलितों और जनजातियों के बीच लोगों का समूह जाकर का प्रचार करता था। इसलिए इन बातों की ठीक से जांच हो। जांच रिपोर्ट में अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हों तो ऐसी खतरनाक भूमिकाओं को रोकने के कदम उठाए जाने चाहिए।

(लेख में विचार निजी हैं)

2024 के चुनाव में हमने देखा कि संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा जैसे झूठ ने भूमिका अदा की। इसमें सोशल मीडिया, मुख्य मीडिया, एआई की पूरी भूमिका थी। दलितों और जनजातियों के बीच लोगों का समूह जाकर का प्रचार करता था। इसलिए इन बातों की ठीक से जांच हो। जांच रिपोर्ट में अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हों तो ऐसी खतरनाक भूमिकाओं को रोकने के कदम उठाए जाने चाहिए

2050 तक भारत में 'एसी' के लिए बिजली की मांग 9 गुना बढ़ेगी

- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के मुताबिक, घरेलू एयर कंडीशनर चलाने के लिए भारत की बिजली मांग 2050 तक नौ गुना बढ़ने का अनुमान है, जो टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन समेत हर अन्य घरेलू उपकरण की वृद्धि को पीछे छोड़ देगी
- पेरिस स्थित एजेंसी के मुताबिक, यह अनुमान पूरे अफ्रीका की मौजूदा कुल बिजली खपत से अधिक है
- आईईए के 'विश्व ऊर्जा आउटलुक' में कहा गया है कि बिजली की खपत पर शीतलन आवश्यकताओं का प्रभाव पहले से ही स्पष्ट है। बिजली की मांग तापमान पर निर्भर करती है, और भारत में इस मांग में तेजी से वृद्धि हुई है

स्रोत : मीडिया इनपुट्स

ट्रंप का दिमाग चल गया या कोई बदला ले रहे हैं? बेड़ियां, सैनिक विमान, ईवीएम विरोध, जवाबी टैरिफ, मेहमान प्रधानमंत्री की उपेक्षा, उपहास और अब आक्षेप भी। कूटनीति में कड़ा रुख दरकार है। मीडिया भी आंख चुरा रहा है। क्रिकेट का खेल कब तक ओट देगा?

ओम थानवी, पत्रकार
@omthanvi

मुद्दा | गिरीश पांडे

कतर से दोस्ती इसलिए है जरूरी

कतर के शेख तमीम बिन हमद अल-थानी की हालिया 17 से18 फरवरी,2025 की दो दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बुलावे पर की गई थी और वह 2015 के बाद दूसरी बार भारत पहुंचे। उन्हें प्रधानमंत्री स्वयं प्रोटोकॉल तोड़ खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे। इससे सहज ही दोनों देशों के बीच संबंधों की उष्णता का पता चलता है। भारत-कतर संबंधों की अहमियत का पता इस बात से भी चलता है कि कतर की आबादी लगभग 29 लाख है, और वहां 8 लाख 35 हजार के आसपास भारतीय मौजूद है।

कहने को कतर क्षेत्रफल के लिहाज से त्रिपुरा के बराबर एक छोटा देश है, लेकिन कतर लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) और पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है और भारत की ऊर्जा की जो भी जरूरतें रहती हैं, उसे काफी हद तक यह छोटा कतर ही पूरा कर रहा है। इसलिए ऊर्जा सहयोग भारत-कतर संबंधों का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। इसके अलावा, वहां जो भारतीय काम करते हैं, वे हर साल भारत को तो अरबों रुपये भेजते ही हैं, साथ ही कतर की अर्थव्यवस्था में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार कतर में यह भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करता है। कतर भारत पर काफी भरोसा करता है। इसलिए चीन और जापान के बाद भारत कतर का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साल 2017 कोई भूला नहीं है जब मिडल ईस्ट के कई देशों ने कतर का बॉयकॉट कर दिया था, उस पर आरोप लगा था कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उसकी धरती से आईएस जैसे संगठन ऑपरेट कर रहे हैं। उस समय सऊदी अरब ने बड़े मिशन के तहत कतर के विमानों की अपने देश में एंट्री तक बैन करवा दी थी, लेकिन भारत ने उस समय समझदारी दिखाते हुए कूटनीति का परिचय दिया जहां पर सिर्फ कुछ समय के लिए कतर के साथ व्यापार को स्थगित किया गया, लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य हुई, फुल स्पीड में फिर ट्रेड को आगे बढ़ाया गया। ऐसे संकट के समय भारत ने कतर को बायकॉट करने के बजाय सहारा देने का काम किया था जिसे कतर भूला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अ-थानी के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा, निवेश, नवाचार, प्रौद्योगिकी,

खाद्य सुरक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण साझेदारी बढ़ाने का फैसला किया है। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और लोगों से लोगों के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत-कतर के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है। इससे व्यापार, निवेश और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती मिलेगी। हाल के वर्षों में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) के देशों में सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कुवैत के बाद कतर पांचवां देश है, जिसके साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में आपसी व्यापार को वर्तमान 14.08 अरब डॉलर से बढ़ाकर 28 अरब डालर करने का लक्ष्य भी रखा है। कतर ने भारत के प्रमुख क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने में रुचि व्यक्त की है। अभी कतर भारत को एलएनजीऔर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, लेकिन अब रणनीतिक साझेदारी के तहत व्यापार इससे आगे भी बढ़ाया जाएगा। इससे आने वाले समय में कतर भी संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत की तरह भारत के करीबी व्यापारिक सहयोगियों में शामिल हो जाएगा। भारत में कतर का मौजूदा निवेश देखें तो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने पहले ही भारत में खुदरा, विद्युत क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, किफायती आवास में 1.5 अरब डालर का निवेश किया है।

भविष्य में बुनियादी ढांचा और बंदरगाह जहाज निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट सिटी फूड पार्क और स्टार्टअप्स, एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग जैसी नई प्रौद्योगिकि निवेश के संभावित क्षेत्र कहे जा सकते हैं। कतर की कंपनियों ने देश के तकनीकी, बुनियादी ढांचे और विनिर्माण उद्योगों में महत्त्वपूर्ण निवेश किया है, जबकि भारतीय कंपनियों ने कतर में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। निःसंदेह कतर के अमीर की भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच एक गहरी और बहुआयामी साझेदारी के लिए मंच तैयार कर दिया है। रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, भारत और कतर महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जिससे उनके लंबे समय से चले आ रहे संबंध और मजबूत होंगे और क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्थिरता में योगदान मिलेगा। हम उम्मीद करेंगे कि भारत और कतर को नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्टार्टिअप के क्षेत्र में और अधिक सहयोग बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए जिससे हेल्थ केयर, ऊर्जा, पर्यटन एवं शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का लाभ दोनों देशों को मिल सके।

श्रद्धा | ओशो

श्रद्धा का अर्थ है, जिसे मानने के लिए तर्क के पास कोई कारण न हो; जिसे मानना बिल्कुल असंभव मालूम पड़े, जिसे मानना बिल्कुल ही अतर्क्य हो उसे मान लेना। जो दिखाई न पड़ता हो, जिसका स्पर्श न होता हो, जिसकी गंध न आती हो, और जिसको मानने के लिए कोई भी आधार न हो उसे मान लेने का नाम है श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा बहुमूल्य सूत्र है। वह अंत नहीं है, शुरुआत है। जिसे तुम मान लेते हो, उसकी खोज की संभावना शुरू हो जाती है। वैज्ञानिक हायपोथिसिस निर्मित करते हैं। श्रद्धा हायपोथिसिस है। हायपोथिसिस का मतलब होता है कि पहले वैज्ञानिक एक सिद्धांत तय करता है, क्योंकि बिना सिद्धांत तय किए तुम जाओगे कहां, खोजोगे कैसे क्या खोजोगे? खोज की शुरुआत ही न हो सकेगी। वह सिद्धांत सिर्फ प्रारंभ है, वह कोई अंत नहीं है, लेकिन उससे द्वार खुलता है, उससे संभावना निर्मित होती है फिर आदमी खोज में निकलता है। हो सकता है वह मिले, हो सकता है न मिले। क्योंकि अंधेरे में तुमने जो तय किया था, उसके मिलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है: हो सकता है, तुमने जो तय किया था वह न मिले; लेकिन कुछ मिलेगा। परमात्मा को तुम अभी जानते नहीं, कोई पहचान नहीं, कभी देखा नहीं, कभी मिलन नहीं हुआ। श्रद्धा का अभी तो इतना ही अर्थ हो सकता है कि हम एक परिकल्पना स्वीकार करते हैं, और हम खोज में लगते हैं शायद जो परिकल्पना है वैसा सिद्ध हो, न हो, लेकिन एक बात पक्की है कि खोज शुरू हो जाएगी। और जिसकी खोज शुरू हो गई, अंत ज्यादा दूर नहीं है। और एक बात यह भी पक्की है कि अज्ञानियों ने जितने ढंग से परमात्मा को माना है, अंतिम अर्थ में वे कोई भी सही सिद्ध नहीं होती; वे सभी परिकल्पनाएं असिद्ध होती हैं। जो प्रगट होता है, वह सभी परिकल्पनाओं से ज्यादा अनूठा है। जो प्रकट होता है वह तुम्हारी सभी मान्यताओं से बहुत ऊपर है। जो प्रगट होता है, तुमने उसे सोचा था दीया; लेकिन जो प्रगट होता है वह महासूर्य है। किसी की परिकल्पना परमात्मा के संबंध में कभी सही सिद्ध नहीं होती, हो भी नहीं सकती। छोटा सा उसका आंगन है कितना बड़ा आकाश उस आंगन में समाएगा? छोटे-छोटे हाथ हैं। इन छोटे-छोटे हाथों से उस विराट को छूने की कोशिश कितना विराट तुम छू पाओगे? बूंद जैसी क्षमता है, सागर को खोजने निकले हो कितना सागर तुम अपने में ले पाओगे?

रीडर्स मेल

महाकुंभ का सफल आयोजन

महाकुंभ केवल एक धार्मिक समागम ही नहीं है, यह भारत की संस्कृति का भी परिचायक है। इस बार महाकुंभ में जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, वह अकल्पनीय है। विश्व में इतने विशाल जनसमूह को आकर्षित एवं नियोजित करने वाले धार्मिक आयोजन की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इससे विपक्षी दल एवं नेता बौखलाये हुए हैं और बेतुके व अनर्गल प्रलाप से न केवल इस आयोजन की सफलता-गरिमा को धुंधलाना चाहते हैं बल्कि सनातन संस्कृति का उपहास उड़ा रहे हैं। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्युकुंभ कहा तो सपा सांसद जया बच्चन एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कहते हैं कि शवों को गंगा में बहा दिया गया, लालू यादव कहते हैं फालतू है महाकुंभ। इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए हैं। महाकुंभ कोई नया आयोजन नहीं है, बल्कि यह वैदिक परंपरा से चला आ रहा है।

संजीव ठाकुर, ई मेल से

जल्द निकालना होगा समाधान

जलवायु परिवर्तन का असर खेती-किसानी पर साफ दिखाई देने लगा है। कहा जा रहा था कि 2024 की फरवरी सर्वाधिक गर्मी वाला महीना रहा है पर 2025 में जनवरी में जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है और फरवरी में ही देश के अधिकांश हिस्सों खासकर उत्तरी भारत में तापमान में लगातार तेजी देखी जा रही है, वह चिंतनीय है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान सहित अनेक प्रदेशों में फरवरी में अधिकतम तापमान का आंकड़ा 30 डिग्री को छूने को बेताब हो रहा है। देश के कई हिस्सों में दिन का तापमान 29 डिग्री को पार कर रहा है। यह कोई हमारे देश के ही हालात नहीं है अपितु दुनिया के अधिकांश देशों में जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिखाई देने लगा है। हालात गंभीर चिंतनीय होते जा रहे हैं और अगर यही हालात रहे तो विशेषज्ञों के मुताबिक कृषि उत्पादन में कमी का असर सारी दुनिया को भुगतना होगा। हालात और भी गंभीर हो उससे पहले ही ठोस प्रयास करने होंगे। नहीं तो महंगाई के चलते कई देशों में भुखमरी के गंभीर हालात झेलने से कोई नहीं रोक सकेगा।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, ई मेल से

जिंदा रखें पारिवारिक मूल्य

हमें अपने पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों को फिर से अपनाने की जरूरत है। बच्चों को नैतिक शिक्षा और पारिवारिक महत्त्व का ज्ञान कराना आवश्यक है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पर निर्भरता को कम करना होगा ताकि वास्तविक संबंध मजबूत हो सकें। परिवारों को यह समझने की जरूरत है कि माता-पिता कोई बोझ नहीं, बल्कि अनुभव और आशीर्वाद का भंडार होते हैं। जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। परोपकार और सेवा की भावना को पुनः विकसित करने की आवश्यकता है। 'अर्थ युग' में हम भले ही आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए हों, लेकिन नैतिक और भावनात्मक रूप से दरिद्र होते जा रहे हैं। रिश्तों का मूल्य घटता जा रहा है और संवेदनाएं समाप्त होती जा रही हैं। यदि हमें एक सशक्त और प्रेमपूर्ण समाज की रचना करनी है, तो हमें अपने मूल्यों को पुनर्जीवित करना होगा।

बलदेवराज भारतीय, ई मेल से
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 190
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के वचन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 25 फरवरी 2025

अपराध का जाल

म्यांमार के साइबर क्राइम अड्डों से 70 भारतीयों को जिस तरह छुड़ाया गया, उससे पता चलता है कि यह समस्या कितनी गंभीर है। साइबर अपराधियों का जाल बहुत फैला हुआ है और खत्म करने के लिए साझे प्रयास की जरूरत है।

बाहरी सपोर्ट | साइबर अपराधी अब पहले से ज्यादा संगठित और ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। म्यांमार में ही जो भारतीय फंसे हुए थे, उन्हें नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था। काम और जगह कोई और बताई गई, फिर धोखा देकर साइबर क्राइम में धकेल दिया गया। छुड़ाए गए भारतीयों में गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों के लोग हैं। इतना बड़ा अपराध संगठित नेटवर्क के बगैर नहीं चल सकता। जब तक इस नेटवर्क को खत्म नहीं किया जाता, आम लोग इसके चंगुल में फंसते रहेंगे।

AI Image

साइबर क्राइम कैसे रुके

दबाव बनाया जाए | म्यांमार का म्यावाडी वैसे भी साइबर अपराध के लिए बदनाम है। यहां करीब 2000 भारतीय फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर से जबरदस्ती ऑनलाइन ठगी कराई जा रही है। अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उसे म्यांमार की बॉर्डर गार्ड फोर्स ने अंजाम दिया है। भारत और दूसरे देशों को इस मामले में म्यांमार का सहयोग लेना चाहिए और जरूरत पड़े तो मदद करनी चाहिए ताकि इस अड्डे को पूरी तरह खत्म किया जा सके। यहां दूसरे मुल्कों के लोग फंसते ही नहीं हैं, बल्कि यहीं से उन मुल्कों के लोगों को फंसाया भी जाता है।

अर्थव्यवस्था पर चोट | अनुमान है कि इस साल तक साइबर क्राइम की वजह से होने वाला नुकसान 10 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो सकता है। 10 साल पहले यह आंकड़ा 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था। यानी, साइबर अपराधियों ने इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली है, जिसकी यदि देशों से तुलना की जाए तो तीसरे नंबर पर आएगी। यही पैसा फिर आतंकवाद और अराजकता फैलाने में इस्तेमाल होता है।

जागरूकता की जरूरत | जून 2022 के बाद से म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड से 600 से अधिक भारतीयों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इसका मतलब है, साइबर क्रिमिनल्स पर फुटकर हमलों का असर नहीं हो रहा। वे पहले की तरह ही आम लोगों को जरिया बनाकर आम लोगों को ठगने में लगे हुए हैं। इसे खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पहल की जरूरत है।

धूप-छांव

ये जो दो जमातें हैं...

प्रणव प्रियदर्शी

किसी समझदार ने यह बात कही है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के भेदों से अलग हटकर देखें तो दो तरह की जमात होती है लोगों की। एक जो जानते हैं और दूसरे जो मानते हैं। इन दो जमात को पहचानने के लिए ऊपर बताए गए भेदों से अलग हटने को क्यों कहा गया है? इसलिए कि इन दोनों वर्गों के लोग हर समूह में मिल जाते हैं। तो होता यह है कि उन पारंपरिक भेदों के दायरे में रहते हुए देखें तो बाकी सब कुछ दिखता है लेकिन ये दो जमातें नहीं दिखतीं। वैसे यह विभाजन भी थोड़ा उथला ही है। आगे बढ़ने पर कन्फ्यूज कर सकता है। इसलिए थोड़ी और सटीकता लाते हुए यह कहा जाए कि जानने की कोशिश करते रहने वाले लोग और मान लेना काफी समझने वाले लोग।

जानने वाले समझते हैं कि जानना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। इसलिए वे जानने का कोई भी मौका और तरीका छोड़ते नहीं हैं। जानने के प्रयास में अगर जरूरत हुई तो मान भी लेते हैं कभी-कभी। यह सोचकर ठिठकते नहीं कि ऐसा करने से मानने वालों की जमात में शामिल हो जाएंगे। किसी जमात में गिने जाने से ज्यादा बड़ी बात उनके लिए होती है जानना। सो, अगर मानकर जाना जा सकता है तो मान लेने में उन्हें कोई हर्ज नहीं दिखता। उस वर्ग में उनके आसपास खड़े दूसरे लोग अपनी मान्यता से आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं महसूस करते जबकि ये लोग जानने के चक्कर में मानी हुई बातों पर भी सवाल उठाते रहते हैं।

समूह चाहे धार्मिक हो, वैचारिक हो या सांस्कृतिक हो, उसके अंदर इन दोनों वर्गों के लोगों में टकराव हमेशा चलता रहता है। खास बात यह कि जानने वालों को मानने वालों से खास दिक्कत नहीं होती। मगर मानने वाले जानने वालों को दुश्मन माने रहते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके यकीन, उनकी मान्यता को चुनौती इन जानने वालों के बीच से ही मिलती है। तो रास्ता क्या है? क्या हो सकता है सिवाय इसके कि जैसे बाकी सब भेदभाव के लिए गुंजाइश रखी है वैसे ही हर समूह में थोड़ा स्पेस इन जानने वालों के लिए भी रखा जाए। बेशक ये अपनी खुराफात नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन खुराफातों से ही मानने वालों की राह भी दिलचस्प बनती है, उसमें नए-नए सरप्राइज की संभावनाएं उगती हैं।

बोल वचन

गोंड़रा पर गौनही

राहुल पाण्डेय

शहरों में बैठने के लिए कुर्सियां होती हैं। कुर्सियां गांव में भी होती हैं, मगर वे सिर्फ मान्य के लिए। बाकी सबके लिए या तो पीढ़ा-मचिया होती है, या फिर गोंड़रा। पीढ़ा-मचिया तो सभी जानते हैं, और हो सकता है कि बहुतों ने गोंड़रा देखा हो- उसके नाम से अपरिचित हों। गोंड़रा पुआल से बना गोल चौका होता है। फसल जब कटकर घर आती है तो उसकी चिनाई-धुनाई-बिनाई जैसे बहुतेरे काम होते हैं, जो किसान गोंड़रे पर ही बैठकर करते हैं। गोंड़रे पर बैठकर गौनही गाते-गाते स्त्रियां चटपट सारा काम निपटा देती हैं। जब तक चारा काटने वाली मशीन नहीं आई थी, कब्बी गंड़ासे से काटी जाती थी- गोंड़रे पर बैठकर। लेकिन गोंड़रा सिर्फ पुआल का गोल चौका ही नहीं होता है। यह चरसे का मंड़रा भी होता है, यानी भांग के पौधे से निकलने वाला गोंद। इसका सेवन इंसानों के अलावा तोते जैसे कुछ पक्षी भी करते देखे गए हैं। वैसे तोते तो अफीम की गोंद देखकर पगला जाते हैं। पर ये सब तो इसे अवध में मिले अर्थ हैं। मगही में गोंड़रा कान का कुंडल या उसकी तरह की कोई और वस्तु भी हो सकता है। यही नहीं, बिना रीढ़ या हड्डी की मछली यानी झींगे को भी गोंड़रा कहते हैं। अंग्रेज लोग गोंड़रा पर कभी नहीं बैठे और शायद इसीलिए इस शब्द की इंग्लिश उनके शब्दकोश में भी नहीं मिलती।

AI Image

भारत में दुनिया को आध्यात्मिक परिवर्तन का रास्ता दिखाने की क्षमता हमेशा से रही है

कुंभ में जुटी भारी भीड़ का क्या अर्थ है

अवधेश कुमार

प्रयागराज महाकुंभ संपूर्ण विश्व के लिए अगर आश्चर्य का विषय बना है तो यह स्वाभाविक है। इतिहास के किसी भी दौर में विश्व समुदाय नदी या नदियों के संगम में डुबकी लगाने के लिए इस तरह से जन समूह उमड़ने के दृश्य का साक्षी नहीं बना। कोई यह सोचे कि इतना बड़ा जनसमूह निकलकर यूं ही आ गया, डुबकी लगाकर अपने घर लौट गया और इसका कोई परिणाम तात्कालिक और दूरगामी दृष्टि से नहीं होगा तो यह सही सोच नहीं होगी। ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं तो उनके परिणाम लंबे समय तक आते रहते हैं। भले ही तुरंत उन्हें समझना संभव नहीं होता।

पश्चिमी सोच की सीमा | दुर्भाग्य से हमने पुनर्जागरण, परिवर्तन, क्रांति, धर्म, कर्मकांड, जीवन-मृत्यु, सुख आदि के बारे में पिछले करीब डेढ़ सौ वर्षों में पश्चिमी नजरिये से अध्ययन किया। उदाहरण के लिए, पुनर्जागरण को हम यूरोप के रेनेसां वाले दौर से देखते हैं। पश्चिम ने हमेशा राजनीतिक क्रांति को परिवर्तन का मूल माना।

क्रांति की भारतीय सोच | भारत ने धार्मिक-आध्यात्मिक-सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात की। यहां क्रांति का अर्थ ऐसे परिवर्तन से है जो व्यक्ति से निकलते हुए समाज, राष्ट्र और विश्व तक पहुंचता है। अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद ,स्वामी दयानंद आदि ने हमेशा भारत की आध्यात्मिक क्रांति की सोच को सामने रखा।

महाकुंभ में इस बार उमड़ा श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब

> **दुनिया है दंग**
> - विश्व समुदाय कभी ऐसे दृश्य का साक्षी नहीं रहा
> - भारत में राजनीतिक क्रांति की अवधारणा नहीं
> - आध्यात्मिक परिघटनाएं ही परिवर्तन का वाहक

परिवर्तन के वाहक | भारत में जब-जब समस्या हुई कोई शंकराचार्य, कोई रामानुजाचार्य, कोई महात्मा बुद्ध परिवर्तन के वाहक बने। उन परिवर्तनों का गहरा असर आज तक है और यही भारत को बचाए भी रहा। इसी भाव को भारत में फिर से पैदा करने की आवश्यकता थी। भारत इस रूप में बदल रहा है और विश्व में उसके उत्थान का समय है। अंग्रेजों से स्वतंत्रता संघर्ष के समानांतर अनेक संगठन संस्थाएं इसी दृष्टि से खड़ी हुईं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार स्वयं बंगाल में क्रांतिकारी थे, किंतु वापस आकर उन्होंने संघ की स्थापना की। उसके पीछे भारत में इसी अमूर्त क्रांति और परिवर्तन का लक्ष्य पाने और उसे बनाए रखने का भाव था।

भारतीय जीवन का मूल | वास्तव में, धर्म भारतीय जीवन का मूल रहा है। अंग्रेजों ने वाइट मैंस बर्डन थियरी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दी और हमने कृण्वंतो विश्व आर्यम् संपूर्ण मानवता को ज्ञान देने के लिए। हमारे लिए यही पुनर्जागरण और वैश्विक क्रांति है। उसके लिए खगोलीय दृष्टि भी थी। यानी किस तिथि, किस काल में कौन सा कर्मकांड करने पर दिव्य शक्तियां हमें सकारात्मक परिणाम देंगी, इसकी सूक्ष्मतम गणना थी। इसी गणना के अनुसार कुंभ सहित हमारी बाकी धार्मिक परंपराएं निर्धारित रहीं।

भारतीय कसौटी | राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी BJP या मोदी-योगी सरकारों की जितनी आलोचना करें लेकिन भारतीय कसौटी पर यह शासन इतिहास के परिवर्तन के उस अध्याय में सदा याद किया जाएगा, जिसने महाकुंभ के प्रचार से लोगों में वहां तक पहुंचने का भाव पैदा किया।

राजसत्ता का कर्तव्य | महाकुंभ के प्रचार का राजनीतिक विरोध करने वाले जानते ही नहीं कि भारतीय राजसत्ता का यही परम कर्तव्य है। हम मौजूदा शासन के किसी पहलू की भले आलोचना करें, पर भारतीय दृष्टि से इस धार्मिक-आध्यात्मिक-सांस्कृतिक क्रांति का वाहक मोदी और योगी सरकार बनी है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और विचारक हैं)

लाइफ़स्टाइल बदल लो भाई, सब ठीक हो जाएगा

अखिलेश प्रताप सिंह

उनने कहा, नर्सरी एडिमशन शुरू होने वाले हैं, ये स्कूल वाले फिर से फीस बढ़ाएंगे भाई साब। आम आदमी करे तो क्या करे? मैं मेट्रो में सीनियर सिटिजन वाली सीट पर जमा हुआ था और इस गुंताड़े में था कि अधपके बाल तो सीट बचाने के काम आ जाएंगे, पर सामने बैठी सुंदरी को किस तरह इंप्रेस किया जाए। लेकिन उनकी बात से ध्यान भंग हो गया। बहरहाल, उन साहब की बातें सुनकर मैं फौरन ही प्रवचन की मुद्रा में आ गया। मौका बन गया था। सुंदरी भी इंप्रेस हो सकती थी। बल्लेबाज खुद फंसने को तैयार था। मेरे चेहरे पर मन की बात समझ लेने वाली मुस्कान थी।

वह शुरू हो गए। जान हथेली पर रखकर बेटे को कोचिंग सेंटर के अखाड़े में भेजा था। जान, हथेली, अखाड़ा? मैंने टोका। अखाड़ा तो कुश्ती का होता है। और जान-वान का किस्सा तो हमारे यहां होता नहीं। रोम में होते थे जान लेने वाले अखाड़े। वहीं लोग लड़ाते थे ग्लैडिएटर। कहीं पढ़ा था, एक ही जिंदा वापस आता था।

ग्लैडिएटर की बात सुनकर उनका चेहरा कुछ सख्त होने लगा। बुदबुदाने लगे स्पार्टाकस, हॉवर्ड फास्ट, आदि विद्रोही। उनकी मुट्ठियां कसने लगीं। मैंने तुरंत ही उनके कंधों पर हाथ रखा। भाई साहब, क्या हुआ?

AI Image

गुस्ताख़ी माफ़

किस बात पर गुस्सा हो गए? नारे-वारे लगाओगे क्या? लंबी सांस लो। मन शांत होगा।

कुछ नहीं, बस आपने स्पार्टाकस का नाम लिया तो जवानी के दिन याद आ गए। नारे-वारे तो तब लगाता था मैं, अब क्या लगाऊंगा। अकबर इलाहाबादी का दौर होता तो और बात थी। महाकुंभ के दौर में तो कब कहां भगदड़ मच जाए, कौन जाने। पता ही नहीं चल रहा कि इलाहाबादियों के चक्कर में समय फंस गया है या समय के फेर में इलाहाबादी।

समय हमारे कंट्रोल में नहीं होता भाई साब। अच्छा-बुरा आता रहता है। इसकी चिंता न करो। मैंने उन्हें शांत करने के लिए कहा। आप सुनाओ, क्या कह रहे थे? उन्होंने मेरी ओर भरपूर निगाह डाली और शुरू हो गए। ऐसा लगा कि मोहल्ला क्लीनिक की भीड़ में बहुत दिनों बाद उन्हें कोई असल चारागर मिला है।

उनका बेटा अखाड़े से सही-सलामत लौटा। लेकिन बीटेक के बाद भी उसकी नौकरी का एल्गॉरिद्म नहीं सुलझ रहा। कहने लगे, बिटिया दसवीं में है। उसके स्कूल वाले अलग ही रायता फैलाते रहते हैं। कभी कहते हैं कि महिला शक्ति का रूप होती है, कभी कहते हैं कि महिला को पुरुष के संरक्षण में रहना चाहिए।

भाई साहब, 10 हजार रुपये महीने तो उसकी स्कूल फीस हो गई है। बेटा बीटेक में गया, तो लगा कि सहारा हो जाएगा। सालभर हो गए, नौकरी ही नहीं मिल रही। आप कह रहे थे न कि नारे लगाएंगे क्या? अब तो नारों से भी असर नहीं पड़ता।

खतरनाक लग रहा था यह आदमी। इसको गुस्सा बहुत आता है। अच्छे काम का अच्छा। इस जन्म में न सही, अगले में सही, भला तो होगा ही। किसको नहीं है परेशानी? सबका विकास होगा तो आपका भी होगा। यह उम्र स्ट्रेस लेने की नहीं है। कोई कोर्स कर लो आप, मानसिक शांति बहुत जरूरी है। गुस्सा आए तो लंबी सांस लो भाई साब। लाइफस्टाइल बदल लो। सब ठीक हो जाएगा।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें www.speakingtree.nbt.in

महाशिवरात्रि का संदेश- दाता बनें; दुआ बांटते चलें

ब्रह्मा कुमारी शुक्ला

शिव शब्द अपने आप में शुभता और मंगल का प्रतीक है। शिव संकल्प का अर्थ है ऐसा संकल्प, जो सदा और सभी के लिए कल्याणकारी हो। जिसमें हर क्षण शुभ भावना और शुभ कामना का स्पंदन हो। इसी अनंत शुभता के शाश्वत स्रोत हैं सदाशिव निराकार परमात्मा, जो प्रेम, शांति और करुणा के अविनाशी स्रोत हैं।

आज, जब चारों ओर दुख, कष्ट और अशांति का वातावरण है, ऐसे में हर व्यक्ति को इन दिव्य शक्तियों और दुआओं की नितांत आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें आत्मिक दृष्टि को अपनाना होगा। हर व्यक्ति को उसके मूल स्वरूप में देखना होगा। महाशिवरात्रि का सच्चा संदेश है, आत्मा और परमात्मा के बीच के पावन संबंध को फिर से जागृत करना। जब हम हर व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखते हैं, तो हमारे भीतर स्नेह, रहम और करुणा की धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। चाहे किसी व्यक्ति के संस्कार कितने भी कठोर क्यों न हों, उसके प्रति हमारी शुभ भावना, शुभ कामना और परिवर्तन की दृढ़ संकल्प शक्ति उसके नकारात्मक संस्कारों को धीरे-धीरे नरम करने लगती है। यदि हम हर व्यक्ति के साथ आत्मिक दृष्टि अपनाते हैं, तो जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो आत्मा, आत्मा से मिल रही है और संवाद कर रही है। हर व्यक्ति यदि आत्मिक भाव में रहते हुए बोले, चले तो जीवन का हर मोड़ सहजता से सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है।

जीवन में सच्ची खुशी और सफलता का रहस्य है, दुआएं देना और दुआएं लेना। सेवा किसी विशेष अवसर तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे प्रतिदिन के व्यवहार और विचारों में समाई होनी चाहिए। हम चाहे सांसारिक कार्यों में कितने भी व्यस्त क्यों न हों, यदि हमारी दृष्टि, वृत्ति, शब्द और भावनाएं दूसरों को दुआएं देने में लगी रहती हैं, तो यह न केवल उनके जीवन को रोशन करती हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी आंतरिक सुख और शांति से भर देती हैं।

सच्ची आत्मिक सेवा यही है कि हम स्वयं दाता बनें। जब हम इस भावना के साथ जीवन जीते हैं, तो न केवल हमारे भीतर शांति और खुशी का अनुभव होता है, बल्कि परमात्मा से अनगिनत आशीर्वाद भी प्राप्त होने लगते हैं। यही आशीर्वाद जीवन में खुशियों का संचार करते हैं और कठिनाइयों के समय हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। सच्चा आध्यात्मिक साधक वही है, जो चुनौतियों से घबराता नहीं, बल्कि उचित समय पर जरूरतमंद की मदद करता है और दिल से दुआ देता है। महाशिवरात्रि का संदेश भी यही है कि हम दाता बनें, याचक बनकर न रहें। याद रखें, शिव को औघड़दानी कहा गया है।

विशुद्ध राजनीति

पॉलिटॉक

थरूर के मन में क्या है

पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर के बयानों को लेकर काफी चर्चा है। अगले साल केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी से नाराजगी कांग्रेस के लिए नई मुसीबत बन रही है। पिछले दिनों कांग्रेस नेतृत्व ने उनसे मुलाकात भी की, लेकिन इसके बाद उनकी नाराजगी और बढ़ गई। थरूर पार्टी में अहमियत चाहते हैं। उनका मानना है कि उन्हें पार्टी में इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन पार्टी उन्हें कोई पक्का आश्वासन देने को तैयार नहीं है। कुछ नेताओं को लगता है कि वह खुद को केरल में सीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। इन सबके बीच शशि थरूर कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर देते हैं तो कभी केरल की लेफ्ट सरकार के कामकाज की। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डालते हैं, जिसे नेतृत्व पर निशाना माना जाता है। हालांकि जब से वह राजनीति में आए हैं तभी से उनका रवैया किसी मेनस्ट्रीम राजनेता की तरह नहीं रहा है। थरूर के करीबी इसे उनकी मजबूती भी मानते हैं। लेकिन इस बार पार्टी नेतृत्व से हो रहा उनका टकराव किधर जाएगा, वह अगले कुछ दिनों में साफ हो पाएगा।

सक्रियता से सस्पेंस

पूर्व केंद्रीय मंत्री और BJP के सीनियर नेता आरके सिंह के एक बयान के बाद सस्पेंस पैदा हो गया है। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कह दिया कि उन्हें लोकसभा चुनाव में उनके ही दल के नेताओं ने हराया। जब उनसे दोबारा पूछा गया तो उन्होंने वही बात फिर दोहरा दी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आए उनके इस बयान के बाद BJP संभावित परेशानी को दूर करने में लग गई है। वैसे बयान तो अपनी जगह है ही, आरके सिंह पिछले कुछ दिनों से काफी सक्रिय भी दिख रहे हैं। वह अपने लोगों से लगातार मिल रहे हैं। उनके लोग संकेत दे रहे हैं कि वह कुछ बड़ा सोच रहे हैं। पिछले दिनों उनकी ओर से एक सामाजिक संगठन बनाने की भी चर्चा थी। इन खबरों के बीच अब BJP उन्हें मनाने की कोशिश करने लगी है। लेकिन उनकी शर्तें सुनकर पार्टी पशोपेश में है। सूत्रों के अनुसार अगर उनकी मांगें मानी जाती हैं तो बाकी लोग नाराज हो सकते हैं। अगर उनकी मांगें नहीं मानीं, तो पार्टी को चिंता है कि कहीं वह थरूर के नक्श-ए-कदम पर न चलने लगें।

आरोपों का फायदा

अभी असम में हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी पर कई संगीन आरोप लगाए। इसके बाद गौरव गोगोई ने इसका जवाब दिया। अब कांग्रेस को लगता है कि इस विवाद का लाभ गौरव गोगोई को हुआ। पार्टी इस आकलन में जुटी है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में गौरव गोगोई को सीएम उम्मीदवार के रूप में उतारकर चुनाव को हिमंता बनाम गौरव किया जाए, तो पार्टी को इसका कितना फायदा या नुकसान होगा। पार्टी हर लेवल पर इसके लिए माथापच्ची कर रही है।

प्रियंका की आड़ में

कांग्रेस संगठन में इन दिनों फेरबदल हो रहे हैं। इस बीच पार्टी में एक बड़े बदलाव की चर्चा है। पार्टी चुनाव मैनेजमेंट से जुड़ी एक अलग बॉडी बनाएगी, जिस पर चुनावों और पार्टी की तैयारियों को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी होगी। चर्चा है कि इस नए विभाग की मुखिया पार्टी नेता और सांसद प्रियंका गांधी बन सकती हैं। अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा कि इस विभाग को बनाने और प्रियंका गांधी को इसकी जिम्मेदारी देने से कई चीजों का समाधान एक साथ हो जाएगा। अगर यह विभाग बनता है कि तो इसके प्रमुख की ताकत संगठन महासचिव से अधिक हो सकती है। साथ ही, चुनाव से जुड़े तमाम फैसले, जो अभी संगठन महासचिव के पास हैं, इस विभाग के पास आ जाएंगे। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से पार्टी का एक वर्ग संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। इन नेताओं का मानना है कि उनका पूरा फोकस सिर्फ नेतृत्व को अपने पक्ष में करने पर रहता है। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी एक समानांतर भूमिका में आती हैं तो इन नेताओं की अहमियत बढ़ सकती है।

रेवड़ी पर दुविधा

दिल्ली विधानसभा चुनाव में BJP को बड़ी जीत मिली। इस जीत के पीछे एक वजह लाडली बहन स्कीम का वादा भी था, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाने हैं। अब सबकी नजर इस पर है कि योजना को कब लॉन्च किया जाएगा। कहा जा रहा है कि आठ मार्च को महिला दिवस के मौके पर इस स्कीम को लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन एक दुविधा भी है। विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस और RJD अभी से इस बात के लिए दबाव बनाने लगी हैं कि अगर दिल्ली की महिलाओं को इसका लाभ मिलता है तो बिहार में भी मिले। तेजस्वी यादव ने पहले ही इसके लिए चुनावी वादा कर दिया है। अब दुविधा है कि बिहार की आर्थिक स्थिति ऐसी है ही नहीं कि वह महिलाओं को हर महीने इस तरह की राशि दे सके। लेकिन फीडबैक है कि अगर वहां योजना को लागू नहीं किया गया, तो इसका सियासी नुकसान हो सकता है।

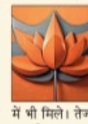

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ एयर इंडिया ध्यान दे

24 फरवरी का संपादकीय 'सर्विस दुरुस्त हो' पढ़ा। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि एयर इंडिया के पैसेंजर्स को आए दिन समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है। मसलन सीट का खराब होना, फ्लाइट के अंदर सफाई की कमी, फ्लाइट का देर से लैंड होना आदि। एक मंत्री की शिकायत पर बात बड़ी हो गई। एयर इंडिया को आ रही शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए। शिकायतें लगातार आ रही हैं तो कहीं न कहीं गड़बड़ी जरूर है। यात्रियों को यात्रा के दौरान सुविधा चाहिए। उन्हें इन बातों से कोई सरोकार नहीं कि सप्लाई चेन में बाधा उत्पन्न होने के कारण विमान के रखरखाव और मरम्मत में देरी होती है। इसलिए एयर इंडिया को चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी सर्विस को दुरुस्त करे।

वारिस अली, ईमेल से

■ सुरक्षा की गारंटी मिले

तेलंगाना की निर्माणाधीन सुरंग धंसने से 8 मजदूर फंस गए। बचाव कार्य चल रहा है। पूर्व में और भी निर्माणाधीन सुरंगों के धंसने की घटनाएं देश में हो चुकी हैं जिनमें मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि जोखिम भरे स्थानों पर सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं. लेकिन इस तरह की चूक बार-बार होना कर्मचारियों की जान से खिलवाड़ जैसी बात है। कंपनियों/सरकारी एजेंसियों को इसे लेकर ठोस कदम उठाने चाहिए।

शकुंतला नेनावा, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

जर्मनी ले रहा 'राइट' टर्न- एक खबर

उम्मीद करें कि जर्मंस के लिए यह टर्न वाकई राइट साबित हो।

पूनम राठौड़

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 8

भारत में टेस्ला की दस्तक

सबसे पहले 2022 और फिर 2024 में नाकामी मिलने के बाद आखिर इस साल की दूसरी तिमाही में टेस्ला भारत की सड़कों पर उतर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान इसी महीने टेस्ला के मुखिया इलॉन मस्क ने उनसे मुलाकात की थी और शायद उस बैठक ने दुनिया की इस दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी को भारत पर दांव खेलने का हौसला दिया है। टेस्ला के साथ बातचीत को शुल्क पर पुनर्विचार करने के भारत सरकार के कदम का हिस्सा भी माना जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने उनके देश को होने वाले भारतीय निर्यात पर जवाबी ऊंचा शुल्क लगाने की धमकी दी है, जिसके बाद सरकार यह कवायद कर रही है। लेकिन टेस्ला पर सरकार का रुख पिछले साल ही बदलता लगने लगा था, जब उसने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपनियों को पांच साल में पूरी तरह तैयार (सीबीयू) वाहनों की 40,000 तक इकाइयां 15 फीसदी सीमा शुल्क पर आयात करने की इजाजत दे दी थी। इन पर पहले 100 फीसदी सीमा शुल्क लगता था। लेकिन एक साल में 8,000 से अधिक सीबीयू वाहन आयात नहीं किए जा सकते। इसके साथ शर्त है कि वाहन निर्माता कंपनी को भारत में 50 करोड़ डॉलर निवेश करना होगा, जिसमें कारखाना लगाना शामिल है और 50 फीसदी निवेश तीन साल के भीतर करना होगा। खबरें हैं कि टेस्ला भारत में असेंबली कारखाने के लिए जगह और सेल्स टीम के लिए कर्मचारी तलाश रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के इलेक्ट्रिक कार उद्योग को इससे तगड़ा झटका तो नहीं लगेगा।

अभी तो ऐसा होता नहीं लगता। इसकी पहली वजह तो ट्रंप ही हैं, जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के मुखिया मस्क से इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि टेस्ला अमेरिका के बजाय भारत में कारखाना लगाने के लिए निवेश क्यों कर रही है। दूसरी वजह भारत में मांग की स्थिति है। देश में ईवी कार का बाजार बहुत छोटा है और 2024 में महज 2.3 फीसदी बाजार इनके पास था। हालांकि टेस्ला के मॉडलों पर लिखा उसका नाम बहुत कीमती है और खास तरह के ग्राहक उसे खरीदने के लिए दौड़े-दौड़े आएंगे मगर इन ग्राहकों की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि कंपनी को भारत में विनिर्माण कारखाना लगाना पड़ जाए, यह मुश्किल लगता है। कहा जा रहा है कि टेस्ला की सीबीयू कार बर्लिन गीगाफैक्टरी से भारत लाई जाएंगी और शुल्क कम रहने पर भी इनकी कीमत बहुत अधिक होगी।

टेस्ला की कीमतों की बात करें तो इसका साइबरट्रक 50 लाख रुपये का हो सकता है और 5 सीट वाली एसयूवी एक्स की कीमत 2 करोड़ रुपये तक जा सकती है। दुनिया भर में इसका सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल वाई भी यहां 70 लाख रुपये के करीब पड़ेगा। भारत में इलेक्ट्रिक कार की औसत कीमत 6 लाख रुपये से 3 करोड़ रुपये तक है और इस हिसाब से टेस्ला की कारों के औसत दाम काफी ज्यादा बैठेंगे। भारत में सबसे महंगा ईवी रॉल्स रॉयस स्पेक्टर है, जो 7.5 से 7.8 करोड़ रुपये का पड़ता है। मगर ज्यादातर लक्जरी इलेक्ट्रिक कार 1.65 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये के बीच आ जाती हैं। मर्सिडीज को छोड़ दें तो 2024 में अधिकतर ईवी कार कंपनियों की बिक्री या तो ठहरी रही या गिर गई। टेस्ला की बिक्री भी दुनिया भर में घट रही है, इसलिए भारत पर उसका दांव भी मुश्किल ही होगा। उसके लिए पासा पलटने वाली बात एक ही है - अगर टेस्ला भारत से हर साल 100 करोड़ डॉलर के पुर्जे खरीदती है। अगर 21 लाख रुपये की कार तैयार करने के मकसद से कारखाने में निवेश करना है तो भारतीय आपूर्ति श्रृंखला में काफी मूल्यवर्द्धन करना होगा। देश में कार उद्योग का उदारीकरण अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए यह दांव ज्यादा बड़ी क्रांति ला सकता है।

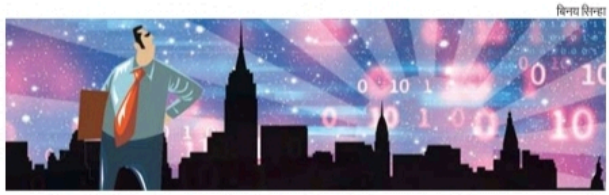

विनय सिन्हा

लोकतंत्र विरोधी मुहिम का भारत पर असर

अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, उसके भू राजनीतिक पहलू का भारत पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। समझा रहे हैं श्याम सरन

अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वहां की सरकारी अफसरशाही के लगभग सभी स्तंभ ढहते जा रहे हैं और इस काम में उनका साथ दे रहे हैं अरबपति कारोबारी इलॉन मस्क। मस्क नए सरकारी दक्षता विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डोज) के मुखिया हैं। यह समझना जरूरी है कि अमेरिका में हो रही इन घटनाओं के पीछे मूल विचार क्या है। इनमें से अधिकतर विचार उन बुद्धिजीवियों के हैं, जो 'टेक्नो-ऑप्टिमिस्ट' यानी तकनीक पर यकीन करने वाले आशावादी हैं। उन्हें लगता है कि अभूतपूर्व और सार्वभौमिक मानव प्रगति का रास्ता तकनीकी प्रगति खासकर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) से होकर गुजरता है। वे कहते हैं कि तकनीकी प्रगति होनी ही है और इसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए इसे धीमा करने या इसकी राह में बाधा डालने के बजाय इसका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।

जांच-पड़ताल और नजर रखने की अवधारणा वाले लोकतंत्र को पुराना बताकर नकारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि तकनीकी प्रगति को रोकता है। ऐसी सोच ने 'डार्क एनलाइटेनमेंट' यानी अंधकारमय ज्ञान के विचार को जन्म दिया है, जो 16वीं सदी के यूरोपीय पुनर्जागरण से शुरू हुई उदारवादी प्रगति और मानवीय एवं उदात्त मूल्यों को अपनाकर 18वीं सदी में हुए ज्ञानरण से आई प्रगति के खिलाफ है। इस शब्द को ब्रिटिश विद्वान निकोलस लैंड सबसे पहले हाई-टेक शब्दावली में लाए थे और पीटर थिएल जैसे सिलिकन वैली उद्यमियों ने इसे लपक लिया। 'एक्सीलरेशनिज्म' इस डार्क एनलाइटेनमेंट का ही एक पहलू है, जो कहता है कि तकनीक खासकर एआई आज की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में भारी रचनात्मक विनाश करेगी और व्यापक राजनीतिक तथा सामाजिक उथलपुथल लाएगी। इसलिए बेहतर है कि बदलाव की इस प्रक्रिया को तेज कर इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए चाहे वह अंजाम कैसा भी हो। इसका रिश्ता 'सिंगुलैरिटी' से भी है, जो रे कर्जवेल की थारणा है। कर्जवेल मानते हैं कि हम उस बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं, जहां एआई मानव मेधा से आगे निकल जाएगी और उसका अपरिमित विस्तार होता रहेगा। कर्जवेल उस स्थिति का स्वागत कर रहे हैं, जो कई लोगों को भयावह और कष्टकारी भविष्य लग रहा है। समस्या यह है कि ट्रंप की नीतियों को प्रभावित कर रहे मस्क और सिलिकन वैली की कई शीर्ष हस्तियां इस टेक्नो-ऑप्टिमिज्म के समर्थक हैं बेशक इसके कट्टरतम स्वरूप का समर्थन नहीं करते हों। संघीय सरकारों को भंग करना तथा हर तरह के नियम-कायदों को खत्म करना 'एक्सेलरेशनलिज्म' को लाने का पहला प्रयास है।

लैंड ने तकनीक से आने वाले इस बदलाव से जुड़ी एक अन्य घटना की भी व्याख्या की है, जिसे 'हाइपरस्टीशन' कहा जाता है। इसमें अंधविश्वास और उच्च तकनीकी बदलाव एक साथ चलते हैं। उनके शब्दों में यह 'गल्प और तकनीक का मिश्रण' है। तकनीक जादू तो बन ही रही है सोशल मीडिया की बेलगाम बाढ़ भी ला रही है, जिसमें समांतर और काल्पनिक वास्तविकताएं जन्म लेती हैं। भारत में यह पहले ही दिख रहा है। तकनीक के मालिक अति अभिजात्य विचारों वाले हैं मगर जनता को प्रभावित करने के औजार उनके ही हाथों में हैं, जो राजनीतिक वर्ग को भी आकर्षक लगते हैं। लेकिन जनमानस को वास्तव में नेता प्रभावित नहीं करते बल्कि यह तकनीकी अभिजात वर्ग करता है।

कॉरपोरेट लॉबी हमेशा राजनीति और सरकार को प्रभावित करती रही हैं। किंतु अब वे सरकार चलाना चाहती हैं और चाहती हैं कि पूंजीवादी कॉरपोरेट शक्ति समाज को संगठित करने वाली ताकत बने। राजनेता उनके लिए जरिया भर हैं। यकीन नहीं हो तो ओवल ऑफिस में मस्क का वीडियो देखिए। ट्रंप चुपचाप खड़े हैं, मस्क कैजुअल कपड़े पहने हैं और उनका बेटा देश के सबसे रसूख वाले दफ्तर में दौड़भाग कर रहा है। इसके जरिये जो संदेश दिया जा रहा है वह स्पष्ट है किंतु परेशान करने वाला भी है।

कॉरपोरेट ताकत की बात सिलिकन वैली के पूर्व उद्यमी कर्टिस यारविन ने उठाई है। वह कहते हैं कि सरकारें नाकाम हो चुकी हैं और लोकतांत्रिक सरकारें उनसे भी ज्यादा नाकाम हो गई हैं। अब वे न तो सुशासन दे सकती हैं और न ही वृद्धि-समृद्धि ला सकती हैं। उनकी पसंद ऐसी सरकार है जो किसी ताकतवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगुआई वाली सफल कंपनी जैसी हो और वह मुखिया उसे बिल्कुल अपनी मिलकियत की तरह चलाए। वह आईफोन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इसे ऐपल जैसी कंपनी ही बना सकती थी, जिसका नेतृत्व अपनी मर्जी चलाता है। या अतीत में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कुछ भी हासिल किया हो आज मंगल और उससे भी आगे बस्तियां बनाने का ख्वाब मस्क की स्पेसएक्स ही पूरा कर सकती है और वही भविष्य है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वह यारविन के विचारों से प्रभावित हैं, जिनमें अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान में घर कर चुके तथाकथित डीप स्टेट को उखाड़ने और भविष्य की तैयारी करने वाला विचार भी शामिल है। डीईआई यानी डायवर्सिटी (विविधता), इक्विटी (समता) और इनक्लूजन (समावेशन) की नीतियां निशाने पर हैं, जो किसी भी बहुलवादी लोकतंत्र का अभिन्न अंग होती हैं। अमेरिका में इन्हें त्यागा ही नहीं जा रहा है बल्कि यूरोप की दक्षिणपंथी पार्टियों की भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आव्रजन विरोधी नीतियों से यह एकदम स्पष्ट हो जाता है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए अपने लोगों को विदेश भेजने का भारत का प्रयास इससे बाधित होगा। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल पहले से अलग है। यह सोचना गलत होगा कि पहले चरण में कारगर रहे उपायों को फिर आजमाया जा सकता है। अमेरिकी राज्य की जिस संस्थागत इमारत को अमेरिकी संविधान से मान्यता मिली है, उसकी एक-एक ईंट निकाली जा रही है। निगरानी और जांच परख की व्यवस्था को समाप्त कर साम्राज्यवादी व्यवस्था कायम की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की सफल यात्रा की है। कम से कम वह ऐसे बड़े नुकसान को टालने में कामयाब रहे जो अमेरिका अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहुंचा सकता है। व्हाइट हाउस में जो शानोशौकत भरा दिखावा किया गया, उससे पहले और बाद में भारतीय नागरिकों (अवैध प्रवासियों) के साथ शर्मनाक बरताव किया गया और उन्हें अपमानजनक परिस्थितियों में वापस भारत भेजा गया।

स्वयंभू तानाशाह ट्रंप रूस के नेता व्लादीमिर पुतिन और चीन के शी चिनफिंग से करीबी की बात कहते हैं और मानते हैं कि वे उन दोनों से सौदेबाजी कर सकते हैं। हाल ही में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में वांस ने यूरोप का कद एकदम छोटा कर दिया, जब उन्होंने कहा कि यूरोप के लिए रूस और चीन खतरा नहीं हैं बल्कि यूरोप खुद है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अब यूरोप का साथ नहीं दे सकता। रूस के साथ जंग में यूक्रेन के भाग्य का फैसला करने के लिए जब ट्रंप और पुतिन बात करने बैठेंगे तो यूरोप नजर नहीं आएगा। ट्रंप को लगता है कि दुनिया की समस्याओं का समाधान किसी याल्टा (जहां दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम समय में प्रैंकलिन रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल और जोसफ स्टालिन की बैठक हुई थी) में अमेरिका, रूस और चीन के बीच बातचीत से हो सकता है। ऐसा हुआ तो अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति की आधारशिला कहा जा रहा क्वाड सामरिक कदम भर बनकर रह जाएगा। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसके भूराजनीतिक आयाम भारत पर गहरा असर डालेंगे।

(लेखक भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं)

क्या वाकई आरआरबी की है जरूरत?

सरकार एक राज्य एक आरआरबी योजना लागू करने के लिए एक अधिसूचना तैयार कर रही है। गोवा में एक भी आरआरबी (ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक) नहीं है, इसलिए वहां ऐसा बैंक स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है। सरकार के इस कदम से देश में आरआरबी की संख्या 42 से घटकर 28 रह जाएगी। संख्या 28 भी तभी होगी यदि गोवा में आरआरबी शुरू किया जाएगा। तेलंगाना में 1 जनवरी को आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की 493 शाखाओं का विलय तेलंगाना ग्रामीण बैंक में कर दिया गया, जिससे सरकार की मंशा के मुताबिक संख्या घटकर 42 रह गई। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तीन-तीन आरआरबी हैं। किसी और राज्य में इतने आरआरबी नहीं हैं।

सवाल उठता है कि क्या हमें वाकई आरआरबी की जरूरत है? ग्रामीण भारत में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार में इनकी भूमिका पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इन बैंकों की स्थापना 1975 के अध्यादेश और 1976 के आरआरबी अधिनियम के तहत हुई थी, जिनका मकसद किसानों एवं अन्य ग्रामीणों को कर्ज मुहैया कराना था। अक्टूबर 1975 में पांच आरआरबी की स्थापना हुई थी।

प्रथमा बैंक देश का पहला आरआरबी था, जिसे 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ सिंडिकेट बैंक ने प्रायोजित किया था। प्रथमा बैंक का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में था। शुरुआती चरण में गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित), हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पंजाब नैशनल बैंक द्वारा प्रायोजित), गौर ग्रामीण बैंक और जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक (दोनों यूको बैंक द्वारा प्रायोजित) की स्थापना भी हुई मगर अब इनमें से कोई भी मूल रूप में नहीं बचा है। प्रथमा बैंक का 2019 में मेरठ के सर्व यूपी ग्रामीण बैंक में विलय हो गया और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक सामने आया। अब पंजाब नैशनल बैंक इसका प्रायोजक है। सरकार को 2009 आते-आते महसूस होने लगा कि आरआरबी को पूंजी की जरूरत है। एक समिति ने 2011-12 में 82 आरआरबी में 40 को 2,200 करोड़ रुपये पूंजी दिए जाने की सिफारिश की और उन्हें बनाए रखने के लिए सरकारी पूंजी देने का सिलसिला शुरू हो गया। आरआरबी में केंद्र की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी होती है और 35 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रायोजक बैंक की होती है। बाकी 15 प्रतिशत हिस्सेदारी उस राज्य की होती है, जहां का वह बैंक है। पूंजी देने के साथ ही इस क्षेत्र का पुनर्गठन भी शुरू कर दिया गया। जनवरी 2013 में 25 आरआरबी का आपस में विलय हुआ और 10 नए बैंक बने, जिससे इनकी संख्या कम होकर 67 रह गई। मार्च 2016 तक 10 अन्य आरआरबी का विलय हुआ और अप्रैल 2020 तक यह संख्या कम होकर 43 रह गई। आखिरी विलय जनवरी 2024 में हुआ है। बाकी बचे 42 आरआरबी जमा और कर्ज मिलाकर लगभग 11 लाख करोड़ रुपये संभालते हैं। इनमें करीब 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं और पांच आरआरबी नुकसान में चल रहे हैं। कारोबारी लिहाज से बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक सबसे बड़ा है और कर्नाटक ग्रामीण बैंक सबसे अधिक मुनाफे में चल रहा है।

बैंकिंग साख
तमाल बंद्योपाध्याय

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की जरूरत पूरी करने में आरआरबी की अहम भूमिका रही है मगर देश की तेजी से बदलती वित्तीय व्यवस्था में वे पीछे छूट चुके हैं। 31 मार्च 2023 में 18.5 लाख बैंकिंग करिस्पॉन्डेंट ग्रामीण घरों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रहे थे। इनके अलावा सूक्ष्म वित्त संस्थान, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और फिनटेक इकाइयां भी विकल्प बन गई हैं। तकनीक ने कर्ज पाने और रकम जमा करने की राह में मौजूद बाधाएं खत्म कर दी हैं। इस मामले में ज्यादातर आरआरबी पिछड़ जाते हैं। कुछ आरआरबी की गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) ज्यादा बड़ी चिंता हैं। मार्च 2024 तक उनका सकल एनपीए अनुपात 6.1 प्रतिशत था, जबकि सितंबर 2024 में समूचे बैंकिंग उद्योग के लिए यह अनुपात केवल 2.6 प्रतिशत था। 2019-20 में 5.9 प्रतिशत रहने वाला उनका सकल एनपीए 2023-24 में घटकर 2.4 प्रतिशत रह गया। लेकिन सितंबर 2024 में समूचे बैंकिंग उद्योग का शुद्ध एनपीए 0.6 प्रतिशत ही था। मार्च 2024 तक कम से कम 11 आरआरबी का शुद्ध एनपीए 5 प्रतिशत से अधिक था। आरआरबी से जारी करीब 90 प्रतिशत कर्ज ऐसा है, जिसे चुकाने के लिए नया कर्ज दे दिया जाता है और इस तरह कर्ज की 'एवरग्रीनिंग' चलती रहती है। इससे कई आरआरबी की मुनाफा कमाने की क्षमता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आरआरबी का लागत-आय अनुपात 68 प्रतिशत है, जो बैंकिंग उद्योग के 43 प्रतिशत से बहुत अधिक होने के कारण चिंता पैदा करता है। अधिक एनपीए और परिचालन व्यय भी आरआरबी के मुनाफे पर असर डाल रहे हैं। पूंजी की ज्यादा चिंता नहीं है क्योंकि सरकार ने वित्त वर्ष 2021 और 2023 के बीच इन बैंकों में 10,890 करोड़ रुपये डाले हैं। राज्य सरकारें और प्रायोजक बैंक भी पूंजी देते रहे हैं। मगर मुनाफा नहीं हुआ तो यह सिलसिला कब तक चल पाएगा?

बैंकिंग क्षेत्र की तुलना में आरआरबी में ऋण आवंटन की रफ्तार भी सुस्त है। बैंकिंग उद्योग की तुलना में उनका ऋण-जमा अनुपात भी कम है। यह अनुपात बताता है कि जमा के जरिये हासिल रकम का कर्ज देने में कितने कारगर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि 2023-24 में आरआरबी ने 7,571 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हासिल किया था मगर परिसंपत्ति पर औसत प्रतिफल (आरओए) केवल 0.7 प्रतिशत था, जो वाणिज्यिक बैंकों के मुकाबले आधा ही था। आरओए बताता है कि कोई इकाई कितना मुनाफा कमा पा रही है। आरआरबी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह बैंकिंग जगत में तकनीकी प्रगति के साथ कमदताल नहीं मिला पा रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग में उनका मामूली निवेश उन्हें होड़ में पीछे खींच रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब लोग मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और रकम भेजने की अधिक कारगर प्रणाली इस्तेमाल कर रहे हैं। निजी और सरकारी बैंक बिजनेस करिस्पॉन्डेंट और किफायती तकनीकी साधनों से गांवों में पैठ बढ़ा रहे हैं, जो आरआरबी के लिए सिरदर्द बन रहा है।

संचालन से जुड़ी दिक्कतें हालात को और पेचीदा बना रही हैं। सहकारी बैंकों की तरह ही आरआरबी को स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप से जूझना पड़ता है। कई मौकों पर आरआरबी कर्मचारी और स्थानीय राजनीतिक दलों में तनातनी देखी गई है। इससे उनके लिए सही फैसले लेना मुश्किल होता है और कर्ज वसूलना मुश्किल हो जाता है। आरआरबी के कर्मचारी की तनख्वाह एवं पेंशन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बराबर ही होती है मगर बैंकिंग कामकाज संभालने में वे उतने माहिर नहीं होते।

एक राज्य एक आरआरबी योजना के बजाय सरकार आरआरबी का उनके प्रायोजक बैंक में ही विलय कर सकती थी। इससे आरआरबी के कर्मचारी प्रवर्तक बैंकों का हिस्सा बन जाते, जहां उन्हें ग्रामीण बैंकिंग का बेहतर प्रशिक्षण मिल सकता था। मगर ऐसा करना आसान नहीं होता। इसमें एक समस्या यह भी है कि आरआरबी की सेवा शर्तों के मुताबिक कर्मचारी का तबादला किसी अन्य राज्य में नहीं किया जा सकता।

(लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

प्रगति हेतु नवाचार एवं नवीन प्रौद्योगिकी अपनाना जरूरी

समय की आवश्यकता है कि सहकारी संगठनों का कामकाज पेशेवर ढंग से हो और रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो।

दरअसल, भारत में कई वित्तीय सहकारी समितियां, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के मामले में काफी पीछे हैं, जो बड़े बैंकों और फिनटेक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने की उनकी क्षमता को सीमित कर देती है। सहकारी समितियों को अपनी परिचालन दक्षता बढ़ाने और अपने ग्राहकों के लिए नए उत्पादों एवं सेवाओं की पेशकश करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल संरचना में निवेश करने की आवश्यकता है। भारत में वित्तीय सहकारी समितियों को वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्तीय बैंकों और फिनटेक कंपनियों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है। इससे सहकारी समितियों के लिए ग्राहकों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, विशेष रूप से उन ग्राहकों को जो अधिक उन्नत एवं परिष्कृत वित्तीय सेवाओं की तलाश में रहते हैं। अतः सरकार को डिजिटल इंडिया, भारतनेट और ई-गवर्नेंस जैसी कई योजनाओं के तहत ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की व्यापक योजना बनानी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए अवसर बढ़ रहे हैं, जिन्हें गैर-वित्तीय सहकारी समितियों के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के डिजिटल युग में वित्तीय सहकारी समितियों के लिए प्रौद्योगिकीय प्रवृत्तियों को बनाए रखना और मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग और रिमोट डिपॉजिट कैप्चर जैसी डिजिटल सेवाओं की पेशकश करना अत्यंत आवश्यक है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए अवसर बढ़ रहे हैं, जिन्हें गैर-वित्तीय सहकारी समितियों के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है

टैरिफ मुद्दों का समाधान भारत के पक्ष में संभावित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, तकनीकी, क्वॉड और प्रशांत एशिया क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम खुले हैं। मोदी की इस यात्रा में टैरिफ और अप्रवासी भारतीयों का मुद्दा सबसे महत्त्वपूर्ण था। भले ही ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। किंतु आगामी सितंबर तक होने वाली व्यापार वार्ता में भारत द्वारा टैरिफ मुद्दों को अपने पक्ष में करा लेने की प्रबल संभावना है। अमेरिका से व्यापार वार्ता भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में महत्त्वपूर्ण होगी।

योगेश कर्नावट, अहमदाबाद

व्यापार को नए पंख लगना संभावित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने के साथ ही व्यापार के नए द्वार खोल दिए हैं। मोदी के प्रयासों से ही मोदी -ट्रंप कॉन्फ्रेंस में जारी संयुक्त बयान के अनुसार भारत अमेरिका ट्रेड डील का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2030 तक व्यापार वर्तमान स्तर से दोगुना 44 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव में 10 साल की डिफेंस कॉमर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप होगी। भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील के अंतर्गत भारत में परमाणु रिएक्टर एआई डेटा केंद्र बनेंगे।

वर्षा अग्रवाल, भोपाल

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति भवन में सोमवार को महिला शांति रक्षकों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। महिला शांति रक्षक 'शांति स्थापना में महिलाएं: एक ग्लोबल साउथ परिप्रेक्ष्य' विषय पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य विकासशील देशों की महिला अधिकारियों को एक साथ लाना है।